राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक अखबार

वर्ष : 05 अंक 14
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00/– रु.
UPHIN/2014/67765

क्राइम रिव्यू

साहस सच लिखने का

लखनऊ,
शुक्रवार , 14 सितम्बर 2018
www.crimereview.co.in
www.facebook.com/crimereview
@crimereview2012

संक्षिप्त समाचार

बंगाल में पूर्व आईपीएस के घर से करोड़ों की नकदी

मेदिनीपुर। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने बुधवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी भारती घोष की कथित अज्ञात स्रोतों से हुई आय से अधिक संपत्ति जब्त की है। सीआईडी के सूत्रों ने बताया कि घोष के मेदिनीपुर स्थित आवास से 4.6 करोड़ रुपये की संपत्ति नकद और तीन किलोग्राम सोने एवं गहने बरामद किए जिसे पांच संदूकों में छुपाकर रखा गया था। बरामद संपत्ति को घाटल स्थित अदालत में जमा करा दिया गया। सीआईडी ने पिछले महीने घोष के खिलाफ कथित तौर पर आय के अज्ञात स्रोतों से संपत्तियां अर्जित किये जाने का मामला दर्ज किया था।

पीएम मोदी 17 को कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर 17 सितंबर को वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान वह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दो दिवसीय दौरे का आरंभिक प्रोटोकॉल बुधवार देर शाम जिला प्रशासन को मिलते ही अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दीं। बुधवार को बनारस आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सर्किट हाउस में पुलिस–प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ (शेष पृ. 7 पर). . .

दारोगा और सिपाही डीजीपी को पहचान ही नहीं पाए, हुए निलंबित

नई दिल्ली। गौतमबुद्धनगर की आम्रपाली पुलिस चौकी में डीजीपी पहुंचे तो पुलिसकर्मी न उन्हें पहचान पाए और न ही उनका वाहन. महकमे के सबसे आलाधिकारी के आने पर भी बिल्कुल बेपरवाह रहे. यहां तक कि सैल्यूट भी नहीं ठोका. जब तक उन्हें डीजीपी के बारे में खबर हो पाती, तब तक खिलाफ एक्शन की तैयारी हो चुकी थी. इस पर चौकी प्रभारी और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया. कार्रवाई के पीछे अनुशासनहीनता की बात कही गई है.रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी के पूछताछ करने पर ठीक से दारोगा और कांस्टेबल पेश भी नहीं आए थे. हालांकि एसएसपी ने इस बात को खारिज किया है. एसएसपी का कहना है कि डीजीपी से चौकी प्रभारी और कांस्टेबल ने कोई सवाल–जवाब नहीं किया था.
(शेष पृ. 7 पर). . .

लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था में संवाद बेहद जरूरी : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था में संवाद बेहद जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी जीत का श्रेय अपने जमीनी–स्तर के कार्यकर्ताओं को देती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का आदर्श वाक्य 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुछ दिनों पहले हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक काफी लाभप्रद रही. उन्होंने गुरुवार को 'नरेंद्र मोदी मोबाइल एप' के जरिए पांच लोकसभा सीटों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. इन पांच लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, बिहार का नवादा, झारखंड का हजारीबाग, राजस्थान का जयपुर ग्रामीण और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम शामिल रहा.

मोदी ने कहा, 'बीजेपी देश के हर कोने में फैल गई है.' उन्होंने कहा कि यह सब पार्टी के समर्पित आम कार्यकताओं के योगदान और कड़ी मेहनत की बदौलत है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी जीत का श्रेय बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को देती है.

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्य नैतिकता के आधार पर नेतृत्व का फैसला करती है. मोदी ने कहा कि पार्टी ने साबित कर दिया है कि 'मेरा बूथ, सबसे मजबूत' हर पार्टी कार्यकर्ता का आदर्श वाक्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उत्साह को देखकर खुश हैं।

सपा–बसपा ने विकास के नाम पर केवल विनाश किया है : सीएम योगी

लखनऊ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा और बसपा को निशाने में लिया हैद्य उन्होंने

पाप के गड्ढे हर जगह थे जिससे राज्य का विकास बाधित था और हमने आकर इस राज्य को एक नई दिशा दी

कहा की इन सरकारों ने केवल विकास के नाम पर विनाश किया है। सपा बसपा के पाप के गड्ढे हर जगह थे जिससे राज्य का विकास बाधित था और हमने आकर इस राज्य को एक नई दिशा दी। सीएम योगी बागपत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे।

सीएम योगी ने गन्ना किसानो के बारे में भी बात कीद्य उन्होंने कहा की "हमारी

सरकार ने गन्ना किसानो को अब तक 36 हजार करोड़ रुपये दिए है और बाकी दस हजार करोड़ रुपये हम आगामी 15 सितम्बर तक देने का प्रयास कर रहे है। योगी ने कहा की "हमारी सरकार ने यूपी को एक नई दिशा दी और लगातार इसके विकास के लिए कार्य कर रहे है"।

यूपी है अहम्द्द आपको बता दे की आगामी लोकसभा चुनावो को देखते हुए यूपी सबसे अहम् माना जा रहा है क्योकि यहाँ से अस्सी लोकसभा सीटें आती है। कहा जाता है की यूपी जिसका देश उसका, इसीलिए नरेन्द्र मोदी सबसे अधिक रैलियां यूपी में कर रहे है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार यूपी में विकास के कामो को नई दिशा देने में लगे हैं।

पेट्रोल, डीजल के दामों में नहीं होगी कटौती : पीयूश गोयल

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम को काबू में रखने को लेकर जो रुख अपना रही है वह उचित है क्योंकि इन ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और समस्या कम होने की बजाए जटिल हो जाएगी। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है जबकि विपक्ष पेट्रोलियम ईंधन के भाव में तेजी को लेकर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।

रेल और कोयला मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर सरकार की सोच उचित है और वह समस्या को बढ़ाने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहती। यहां संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में रेल मंत्री गोयल ने कहा, ''ईंधन के दाम को लेकर सरकार का मौजूदा रुख बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा जिससे समस्या सुलझने के बजाए उलझेगी।''

रुपये की विनियम दर में गिरावट के साथ पेट्रोल की कीमत दिल्ली में करीब 80 रुपये जबकि डीजल की कीमत 73 रुपये लीटर के आसपास पहुंच गयी है। ईंधन के दाम में तेजी के बीच उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की जा रही है। केंद्र फिलहाल पेट्रोल पर 19.48 रुपये लीटर जबकि डीजल पर 15.33 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती (शेष पृ. 7 पर). .

राजधानी में निकला मोहर्रम का जुलूस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े से बड़ी अकीदत और

एहतराम के साथ निकाला गया पहली मोहर्रम का जुलूस, जुलूस हुस्सैनाबाद स्तिथ बड़े इमामबाड़े से होता हुआ छोटे इमामबाढ़े में जा कर हुआ समाप्त, जुलूस में शहर की तमाम अंजुमनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शिया समुदाय के तमाम लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद कर के अश्क बहाये। जुलुस में शिया समुदाय की तमाम औरतों, आदमियों वह बच्चों ने भी (शेष पृ. 7 पर). . .

बसपा सुप्रीमो ने महंगाई के लिए मोदी सरकार को ललकारा

लखनऊ। बसपा सुप्रीमों मायावती ने आज मीडिया को सम्बोधित करते हुये कहा कि देश में आये दिन खासकर पेट्रोल एवं डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरुद्ध कल भारत बन्द के तहत् जो विरोध प्रदर्शन किया गया है तो देश में ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए हमारी पार्टी वास्तव में यहाँ मुख्य तौर से बीजेपी व कांग्रेस पार्टी को ही बराबर की जिम्मेवार मानकर चलती है, जिसकी पृष्ठभूमि व सच्चाई यह है कि वर्तमान बीजेपी के नेतृत्व वाली केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार ने, दिनांक 18 अक्टूबर सन् 2014 को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के केवल छः महीने के अन्दर ही पेट्रोल की कीमत की तरह ही डीजल को भी सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर दिया था और तब फिर उस समय अपने इस घोर गरीब, मजदूर व किसान–विरोधी फैसले को भी इन्होंने एक बड़े आर्थिक सुधार

जबाब दो डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों?

के रुप में देश व दुनिया के सामने पेश किया था। मायावती ने कहा कि परन्तु बीजेपी सरकार की उसी चार वर्ष पुरानी जनविरोधी नीति का ही आज परिणाम यह है कि देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस जैसी यह जन–आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पूरी तरह से अनियंत्रित होकर आसमान छू रही है, जिससे हर वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और इस महँगाई के असर से जनता की कमर टूट रही है और देश की लगभग सवा सौ करोड़ व मेहनतकश आमजनता में दिन–प्रतिदिन का संघर्ष काफी मुश्किल होकर अब इनमें काफी त्राहि–त्राहि मची हुई है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि डीजल व (शेष पृ. 7 पर). . .

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना

बलिया। भासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान देते हुए इशारे इशारे में सीएम पर साधा निशाना कहा कि ड्राइवर तो नया है लेकिन इंजन पुराना।

ऐसे में कैसे विकास होगा जनता का यह सोचने वाली बात हैरू जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही यहां तक उन्होंने कहा डालें कि बीजेपी की उलटी गिनती चालू है।

यह पहली सरकार है जिससे जनता इतना जल्दी नाराज हो गई है और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

कल सीएम बस्ती के बाढ़ क्षेत्र में दौड़ा था इतना बवाल हुआ इसकी जिम्मेदार यहां के अधिकारी हैं जो कि सही बात

सीएम तक नहीं पहुंचा रहे हैं।

जनता परेशान है ऐसे में जनता क्या करें उसकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा यही कारण है कि इस सरकार से जनता बहुत नाराज है।

सरकार (शेष पृ. 7 पर). . .

माल्या–जेटली को बात करते देखा था : पीएल पुनिया

नई दिल्ली। 9000 करोड़ लेकर विदेश भागे विजय माल्या के सनसनीखेज आरोपों के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने जांच की मांग करते हुए कई सवाल दाग रहे हैं. राहुल गांधी ने वित्तमंत्री जेटली के इस्तीफे की मांग की है. इस बीच कांग्रेस नेता पी एल पुनिया ने ये कह कर इस मामले में हलचल मचा दी है कि माल्या के देश छोड़कर भागने से दो दिन पहले उन्होंने माल्या और जेटली को सेंट्रल हॉल में बातचीत करते हुए देखा था. पुनिया का कहना है कि (शेष पृ. 7 पर). . .

एसएसी/एसटी एक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी से किया इंकार

लखनऊ। पिछले कुछ समय से देश में एससी/एसटी एक्ट को लेकर काफी बहस और हंगामा हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही इस एक्ट को लेकर दो बड़े आंदोलन भी हो चुके है। लेकिन अब हाल ही में इलाहबाद हाई ने इस मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे दलित समाज में फिर नाराजगी हो सकती है।

दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एससी ६ एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी (नियमित/रूटीन गिरफ्तारी) करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2014 में दिए गए एक आदेश द्वारा समर्थित सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन किए बगैर इन आरोपियो को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय एससी/ एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमे एक एक दलित महिला और उसकी बेटी ने चार लोगों पर उनपर जानलेवा हमला करने एक आरोप लगाए है।

गौरतलब है कि 21 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने पुरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था।

करप्शन के खिलाफ सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 150 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

लखनऊ। यूपी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने 144 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 150 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए है. ये सभी मामले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर निकाय में हुए भ्रष्टाचार, राशन और छात्रवृत्ति वितरण में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए है और पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से लंबित थे.

लेकिन अब इन मामलों में थ्त दर्ज करने के गृह विभाग के आदेश के बाद म्ँ अपने ही थानों में केस दर्ज कर वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा.

गौरतलब है कि सीएम योगी ने 23 अगस्त को गृह विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य स्तरीय सभी जांच एजेंसियों के 400 से ज्यादा लंबित मामलों पर नाराजगी जाहिर की थी और जल्द से जल्द इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे.

सीएम के निर्देश पर ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो 2 महीने के तय समय मे राज्य की सभी जांच एजेंसियों म्ँ, विजिलेंस, सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन के जरिए 400 से ज्यादा लंबित मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.

गृह विभाग का ये आदेश इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है और अब ये तय माना जा रहा है कि अपने रसूख के चलते कई साल तक भ्रष्टाचार के मामलों को लंबित रखने वाले आरोपी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी।

चुनाव आयोग के निर्देश पर नहीं मिलेगा नोटा विकल्प

नई दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से नोटा (छब्ज्।) का विकल्प हटाने को कहा है। चुनाव आयोग ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जारी किए हैं। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) के चुनावों में बैलेट पेपर से उपरोक्त में से कोई नहीं यानि नोटा का विकल्प प्रकाशित नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को राज्यसभा चुनावों में नोटा को अनुपयुक्त बताते हुए चुनाव आयोग की नोटा लागू करने की अधिसूचना रद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये अहम फैसला मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गुजरात कांग्रेस के नेता और मुख्य सचेतक शैलेश मनुभाई पारमार की याचिका पर सुनाया है। याचिका में चुनाव आयोग के राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटा विकल्प सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव (जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव) के लिए है। ये विकल्प अप्रत्यक्ष चुनाव जहां औसत प्रतिनिधित्व की बात होती है (जैसे राज्यसभा चुनाव) वहां लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से एक मत के औसत मूल्यांकन की धारणा नष्ट होगी। (शेष पृ. 7 पर). . .

राजधानी में निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ, हर साल यहां से मिलते हैं सैकड़ों अईएएस/पीसीएस

लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल और समाज कल्याण आयुक्त चंद्र प्रकाश के द्वारा दीप प्रज्वलित कर आईसएस/पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 का निःशुल्क कोचिंग सत्र का शुभारंभ किया है।

पूरे उत्तर प्रदेश से इस बार आईएएस/पीसीएस की तैयारी करने वाले हजारों बच्चों ने छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में भाग

लिया था, जिसमें इस बार 250 अभ्यार्थियों का सेलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर आज गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में समाज कल्याण मंत्री और समाज कल्याण विभाग के तमाम अधिकारियों ने आईएएस पीसीएस कोचिंग का शुभारंभ किया। आपको बताते चलें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आईएएस/पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 की तैयारी हेतु निरूशुल्क कोचिंग सत्र शुभारंभ किया गया है। इसमें इस बार पूरे प्रदेश से 250 अभ्यार्थियों का सेलेक्शन हुआ है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग से 125, अनुसूचित जाति से 113 तथा अनुसूचित जनजाति से 12 में प्रवेश लिया है।

साथ ही बता दें कि छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष (शेष पृ. 7 पर).

300 से अधिक दवाइयों पर लगा प्रतिबंध

लखनऊ.। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुऐ बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन जेनेरिक दवाइयों को लोगों को सिरदर्द, बदन दर्द, सर्दी और बुखार जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जल्द ही ये जेनेरिक दवाइयां बाजारों में मिलना बंद हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में यह जेनेरिक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कंपनियों ने 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं के प्रभाव और दुष्प्रभाव का बिना अध्ययन किए ही बाजार में उतार दिया था। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन जेनेरिक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले से सन फार्मा, सिप्ला, वॉकहार्ट और फाइजर जैसी कई फार्मा कंपनियों को जोरदार झटका लगा है। इसके साथ ही 6000 से अधिक बड़े ब्रांड को तगड़ा झटका (शेष पृ. 7 पर). . .

भाजपा की उलटी गिनती शुरू, देश को जल्द मिलेगा नया प्रधानमंत्री : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 5० सालों तक सत्ता में बने रहने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और अगले 5० हफ्तों के भीतर देश को नया प्रधानमंत्री मिलना तय है। वाराणसी से चलकर यहां आये साइकिल यात्रियों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मंगलवार को कहा कि जनता भाजपा के बोझ से छुटकारा चाहती है।

सरकार की जिम्मेदारी मंहगाई खत्म करने की है लेकिन केन्द्र सरकार ने जब विपक्ष आन्दोलित था, डीजल–पैट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं

मिला। जीएसटी से व्यापारी परेशान हैं। महिलाओं बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। नौजवानों की नौकरी–रोजगार के अवसर बंद हैं। भाजपा अगले 5० साल तक सत्ता में बने रहने का दावा करती है जबकि जनता अगले 5० हफ्तों में ही अपना फैसला दे देगी। देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की नीतियों से लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा ने जनहित में एक भी काम नहीं किया। वह तो ऐसे फैसले करती है, जिससे लोगों को परेशानी हो और उनमें दुरूख पैदा हो। भाजपा की राज्य सरकार पेपर लीक का बहाना कर भर्ती रोक देती है। बिजली विभाग, टयूबवेल कर्मी, पुलिस भर्ती में पेपर लीक का बहाना बन गया।

लोग शुगर से बीमार हो रहे हैं, आप दूसरी फसलें उगाने की भी आदत डालें : सीएम योगी

लखनऊ। देश में लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही देश भर की तमाम राजनैतिक पार्टियों ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके तहत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जगह-जगह जा कर जनता से मिलना और उनकी समस्या सुनने के साथ-साथ अपनी उपलब्धिया गिनना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के बागपत में किसानों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसानों को एक अजीब सलाह भी दे डाली। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे के

शिलान्यास के लिए वैदिक इंटर कालेज में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद किसानों से कहा कि लोग अत्यधिक शुगर के कारण बीमार होते जा रहे हैं इसलिए आप लोग दूसरी फसलें उगाने भी की आदत डालना शुरू कर दे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धिया गिनाते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के एक-एक शहर और गांव में बिजली पहुंचाई है।

उन्होंने राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बसपा की सरकारों ने बिजली देने में बहुत भेदभाव किया था। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी इससे पहले भी एक बार अपने अजीब बयान को लेकर सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने उत्तरप्रदेश के वृंदावन में एक कार्यक्रम में वृंदावन में बंदरो की समस्या से परेशान लोगों से कहा था कि बंदर भगाने हो तो करो बजरंग बली की आरती और पाठ करो।

किसानों की आमदनी पर सरकार की गारंटी

नई दिल्ली। आम चुनाव में जाने से पहले भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बुधवार को एक और कदम उठाया है। कैबिनेट ने किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को आज मंजूरी दे दी। इथेनॉल कीमत बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है, इससे भी किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार ने किसानों की आमदनी को यकीनी बनाने के लिए 16550 करोड़ की बैंक गारंटी का भी प्रावधान किया है।

मंत्री स्वाति सिंह ने बाढ़ पीड़ितों का लिया जायजा

बलिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने मंगलवार को बाढ़ एवं कटान क्षेत्रों का जायजा लिया। ककरघटा में प्रशासन व बाढ़ विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची मंत्री ने ग्रामीणों से कटान सम्बन्धी जानकारी ली। भरोसा दिलाया कि कटान की समस्या का स्थाई समाधान होगा। अगले साल बरसात शुरू होने से पहले मजबूती से कटानरोधी कार्य कराए जाएंगे।

कटान व बाढ प्रभावित गांव क्षेत्र के ककरघटा, नवका गांव में बाढ़ राहत राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। ग्रामीण विशेषकर दर्जनों महिलाओं ने एकस्वर से अपने गांव को बचाने की गुहार लगाई। राज्यमंत्री ने बाढ़ खण्ड के अधिकारियों से कहा कि इस गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही प्रोजेक्ट पर काम होना चाहिए। हर हाल में अगले साल मई से पहले स्थायी समाधान निकाला जाए। पीड़ितों ने यह भी सवाल किया कि इससे पहले भी आश्वासन मिलते रहे लेकिन कोई पहल नहीं हुई। मंत्री ने फिर दोहराया कि अगले बरसात से पहले स्थाई समाधान निकल जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

पुनर्विवाह के बाद भी विधवा पेंशन की हकदार

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने कहा है कि किसी मृत सरकारी सेवक की विधवा पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है। कैट के प्रशासनिक सदस्य प्रवीण महाजन ने यह कहते हुए दिल्ली निवासी रेणु गुप्ता (47 वर्ष) की पारिवारिक पेंशन बहाल करने का आदेश दिया कि गुप्ता ने अपने पुनर्विवाह के बाद अपने पुत्र के नाम पर पारिवारिक पेंशन को अंतरित करने का अनुरोध इसका नतीजा जाने बिना किया। वह पवन कुमार गुप्ता की पत्नी हैं जो मृत्यु के समय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी थे। कैट ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह चार महीने के भीतर रेणु गुप्ता के पुत्र के नाम से उनके नाम पर पेंशन दावे को अंतरित करे।

महमूदाबाद में नये अधिकारियों की नियुक्तियां

महमूदाबाद, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में नौजवान और तेज तर्रार क्षेत्राधिकारी के पद पर अंकित कुमार चार्ज लेते ही कार्य शुरू किये। वहीं राष्ट्रीय हिन्दू संघ युवा मोर्चा में मनोज कुमार(न्यूज रिपोर्टर) को राष्ट्रीय हिन्दू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा डॉ प्रखर प्रभात गुप्ता ,प्रमित मिश्रा राट्रीय उपाध्यक्ष की संस्तुती पर एवं अर्पित श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय हिंदू संघ सीतापुर उत्तर प्रदेश के परामर्श पर विधानसभा अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय हिन्दू संघ विधानसभा क्षेत्र 151 महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश नियुक्त करता हूँ एवं आप की नियुक्ति पर राष्ट्रीय हिन्दू संघ कार्यकारिणी के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 24 तक निरस्त

लखनऊ। गणोश चतुर्थी व मोहर्रम के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्तर के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 24 सितम्बर तक निरस्त कर दी गई हैं। एडीजी अपराध संजय सिंघल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस के अलावा जीआरपी व पीएसी के कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी लागू होगा। इसमें अधिकारियों को विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी मंजूर करने को कहा गया है।

यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में होगी इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना

लखनऊ। प्रदेश को इलेक्ट्रानिक हब बनाये जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में 1000 एकड़ भू-क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स सिटी का प्रस्ताव बनाकर तत्काल प्रस्तुत किया जाये। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने समीक्षा बैठक में दिये।

2 अक्टूबर के बाद नहीं दिखेगी खुले में लोटा पार्टी : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट सोशल

बेसलाइन सर्वे के आधार पर दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा

रेस्पॉन्सबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार अकेले सारे कार्य नहीं कर सकती है.

देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए. इसके साथ ही कहा कि यूपी को दो अक्टूबर को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि बेसलाइन सर्वे के आधार पर दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा. इसके लिए बड़े स्तर पर करीब सवा दो लाख राज्य में स्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें इस अभियान से जोड़ा गया है. इसके बाद में यूपी को यह सफलता मिल पाई है.

उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी, सरकार के पास अपने संसाधन हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उनको भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं. हमारी पहले किसी भी योजना का कोई रोड मैप नहीं था।

डेंगू बुखार काफी तेजी से हो रहा वायरल

कमलापुर- सिधौली (सीतापुर) विकास खंड कसमंडा क्षेत्र छांजन (जहांगीरपुर) और सर्वा में फैले बुखार डेंगू ने दस्तक दी है। प्राईवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक मासूम मरीज में इसके लक्षण पाये गये हैं। जानकारी क्षेत्रीय लोगों में पहुंची तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग मामले में अंजान है। बरसात के बाद क्षेत्र में बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बीमारी के बचाव के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किये गये हैं। इसी बीच डेंगू ने दस्तक देकर क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। छाजन गांव निवासी अशर्फी पुत्र महावीर को कई दिनों से बुखार आ रहा था। स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिला तो अशरफी बताते हैय कि घर में खाने के लाले पड़े है। अब

इलाज कराने के पैसे नहीं है।

डाक्टर जिला अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दिया। इसी तरह संता पत्नी राम कुमार बताती है। करीब पंद्रह दिन से हमारे और हमारे तीनो बच्चो के बुखार की सिकायत है। बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह (1)कल्लू पुत्र कमलेश (2)आदर्श पुत्र कुन्हु (3) विदाई पत्नी लालजी (4) अतुल पुत्र निर्मल कुमार (5)बच्चू पुत्र ब्रज लाल वायरल से अभी गोद्लामऊ ब्लॉक् में चार लोगो की मौत हो गई। बेनीपुर में कई बीमार हैं। जहांगीरपुर में सीजनी बुखार तेजी से फैल रहा है। घर-घर, गली, मोहल्लों में वायरल फीवर के मरीज पाये जा रहे हैं। इनमें अधिक संख्या मासूम बच्चों की है।

बरेली में तैनात डिप्टी एसपी को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश

लखनऊ। एडीजे मुकेश कुमार सिंह ने हत्या के एक आपराधिक मामले में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने वाले बरेली के डिप्टी एसपी सर्किल अॉफिसर, कुलदीप कुमार को गिरफ्तार कर 24 सितंबर को अदालत में पेश करवाने का निर्देश एसएसपी बरेली को दिया है। उन्होंने एसएसपी को भेजे अपने पत्र में कहा है कि यदि इसका अनुपालन नहीं किया गया, तो यह माना जाएगा कि आप भी अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। लिहाजा आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी जाएगी। थाना हुसैनगंज से संबंधित हत्या के इस मामले में तत्कालीन डिप्टी एसपी कुलदीप कुमार की गवाही होनी है, लेकिन पिछले कई तारीखों से वह गवाही के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। जबकि उन पर समन व वॉरंट का भी तामीला है। अदालत का कहना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भारतीय कानून व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है।

गांव वालों को अब राशन के लिए पूरी करनी होगी यह शर्त

लखनऊ। अब गांव वालों को भी डीलर से राशन लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। यह व्यवस्था आगामी माह अक्टूबर से लागू कर दी गई है। इसके लिए गांव के राशन डीलरों पर पोस मशीन पहुंचनी प्रारंभ हो गई हैं।

पहले चरण में प्रदेश के 45 जिलों में गांव की 44231 राशन दुकानों पर मशीनों को लगाया जाएगा बाकी 30 जिलों में करीब 23000 दुकानों पर नवंबर से राशन का वितरण मशीनों के माध्यम से किया जाएगा जहां उपभोक्ताओं को अंगूठा लगाकर राशन डीलर वितरण करेगा।

ट्रांसफार्मर को बदलने को लेकर हुआ विवाद

त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)। थाना लोनीकटरा क्षेत्र के लदई का पुरवा गांव मे लगभग 60 लोगो के बिजली के कनेक्शन थे जो वर्तमान मे 40 लोगो के कनेक्शन है जिनकी बिजली की सप्लाई गांव से कुछ दूरी पर गंगापुर बाजार मे रक्खे 63 आ के ट्रांसफार्मर से हो रही थी।

लगभग डेढ माह पहले तेज बारिश व तूफान से खम्भे व तार टूट गए जिससे बिजली सप्लाई बंद हो गई। जिसकी सूचना जेई को देकर बाधित बिजली सही करने की मांग की गयी। तो जेई द्वारा कहा गया कि की दूरी ज्यादा है ट्रांसफॉर्मर को उठाकर गांव मे रक्खा दिया जाएगा।

बाद मे जेई से मिलकर पडोसी गांव गौरिया का पुरवा निवासी हरिपाल यादव ने अपने दरवाजे के पास ट्रांसफार्मर लगा रहे है पर कोई निस्तारण नही किया गया।

रखवाकर लाइन चालू करवा इसी संबंध मे आज

उपजिलाधिकारी ने समस्या के निस्तारण का दिया आश्वासन

ली जिससे सिर्फ एक ही ब्यक्ति को बिजली मिल रही है। लदई का पुरवा गांव के सभी कनेक्शन धारी एक माह से बराबर विद्युत विभाग हैदरगढ के अधिकारियो के बीच चक्कर 11ध्9ध18 को शुबह गांव के लोगो ने जेई से बात की तो जेई ने सात हजार रुपए की मांग की और कहा मै लाइन मैन को भेज कर लाइन सही करवा रहा हू आप लोग गाडी और पैसे की ब्यवस्था करके जावो मै लाइन मैन भेज रहा हू

पर जैसे ही लाइन मैन ने सटडाउन लेकर गांव वालो के साथ ट्रांसफार्मर लदवाना शुरू किया हरिपाल ने फोन कर डायल 100 चतअ 1729 पुलिस बुला लिया। मौके पर पहुची पुलिस ने रिंकू वर्मा, रामजश वर्मा, आशीष वर्मा को पकडकर थाना लोनीकटरा पहुंचा दिया जिसपर आक्रोशित ग्रामीणो ने थाने का घेराव किया।

थाना प्रभारी ने जेई से बात कर मामले की जानकारी की तो जेई ने किसी भी बात की जानकारी होने से इंकार किया जिसपर आक्रोशित कनेक्शन धारी व ग्रामीण उपजिलाधिकारी हैदरगढ के पास गये।

हजरतगंज चौराहे का नाम बदलनें पर नवाब जाफर मीर ने जताई नाराजगी

लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहे का नाम बदले जाने पर सियासत तेज हो चली है लेकिन नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह का बयान सामने आने से अब कही ना कही नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है।

लखनऊ नगर निगम के फैसले के बाद से जहाँ सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे है तो वही अब नवाबीन ए अवध ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। दरअसल 176 साल पहले इस चौराहे को नवाब अमजद अली खां द्वारा बसाया गया था जिनको हजरत कहा जाता रहा है तब ही से इसका नाम हजरतगंज पड़ा लेकिन अब पूर्व प्रधनमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको अटल चौक करने की बात सामने आयी है।

जिसपर नवाब जाफर मीर अब्दुलाह का कहना है कि आज कल नाम बदलने का दस्तूर चला है, नाम बदलने का काम विकास नही है। अटल जी की जिंदगी में उनकी इज़्जत की नही गयी और 10 साल अटल जी को किसी ने पूछा नही अब ऐतिहासिक चीजों के नाम बदल कर उनके नाम पर किये जा रहे जो सही नही है। अटल जी के नाम पर नए इदारे बनाये जाए किसी और कि विरासत ना खत्म की जाए, इसके साथ ही उन्होंने एक सलह दी कि अटल जी का नाम अगर हजरतगंज से जोड़ना ही है तो हजरत अटल चौक कर दिया जाए तो भी ठीक रहेगा। तो वही नवाब मसूद अब्दुल्लाह कहते है कि 2019 का चुनाव नजदीक है और इसमें सियासत के तहत अटल जी का नाम भुनाने की कोशिश की जा रही है वो इस बात का इकरार भी करते है कि अखिलेश सरकार में लखनऊ जू का नाम बदल कर नवाब वाजिद अली शाह किया गया था।

एमएलसी बुक्कल नवाब ने शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से दिया इस्तीफा

लखनऊ। भाजपा के एमएलसी बुक्कल नवाब ने शिया वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शासन को दिए इस्तीफे में उन्होंने बोर्ड को यूपी का सबसे बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड की संज्ञा दी है। यह भी कहा है कि उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के कहने पर बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को वोट दिया था, जो उनकी गलती थी। साथ ही बोर्ड को भंग करने की मांग भी की है।

बुक्कल नवाब के इस्तीफा देने से एक बार फिर वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही राजनीति गर्मा गई है। अपने त्यागपत्र में उन्होंने आजम खां के लिए भी बेहद आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है, शिया

वक्फ बोर्ड का सदस्य होने के बाद मैंने आज तक बोर्ड की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे तत्काल भंग करने की सिफारिश करते हुए बोर्ड की मेंबरशिप से इस्तीफा देता हूं।

जिस वक्त बुक्कल इस्तीफा देने प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण मनोज कुमार सिंह के दफ्तर पहुंचे, उस वक्त प्रमुख सचिव वहां नहीं थे। इसके बाद एमएलसी ने संबंधित सेक्शन में जाकर अपना त्यागपत्र रिसीव कराया। इस बारे में संपर्क करने पर मनोज सिंह ने कहा, बुक्कल नवाब का इस्तीफा उन्हें मिल चुका है। इसका नियमानुसार परीक्षण करवाने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

उप्र शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने शासन को पत्र भेजकर कहा है कि मजहर अली खां उर्फ बुक्कल नवाब बोर्ड के सदस्य ही नहीं हैं।

एससी/एसटी एक्ट की धारा 14 के वैधता पर सुनवाई जारी

इलाहाबाद। एससीध एसटी एक्ट की धारा 14 की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई जारी है। कोर्ट के समक्ष सवाल है कि एक्ट में किसी आदेश के खिलाफ 90 दिन में अपील करने तथा देरी होने पर इसके बाद 90 दिन की देरी माफ करने का नियम है। तो 180 दिन बीत जाने के बाद कोई फोरम न होने पर आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226, 227 दंप्रसं की धारा 482 की अन्तर्निहित शक्तियों के तहत चुनौती दी जा सकती है या नहीं याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ कर रही है।

राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस मुखिया की नाक के नीचें लाखों की चोरी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ मे चोरों के हौंसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उनको किसी का खौफ नही रहा। अब पुलिस मुखिया के कार्यालय और आवास के आसपास के हिस्से भी चोरों की रडार पर हैं यही वजह है कि डीजीपी ऑफिस से चंद कदमो की दूरी पर बनी ऑफिसर्स कालोनी मे चोरों ने लाखों की चोरी कर हाई सेक्योरिटी जोन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कृषि विभाग की उपनिदेशक के घर को चोरों ने दिनदहाड़े अपना शिकार बनाया और लगभग 30-40 रूपये लाख का गहना चोरी करके आराम से फरार हो गये। पीड़ित उपनिदेशक ने इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड टीम छानबीन मे जुट गई।

पूरा मामला हजरतगंज थाना क्षेत्र के डालिबाग स्थित

ऑफिसर्स कालोनी का है। डीजीपी मुख्यालय से चंद कदमो की दूरी पर ऑफिसर्स कालोनी है, जिसमे कृषि विभाग की उपनिदेशक शोभा रानी श्रीवास्तव अपने पति के साथ रहती हैं। जब वह अपने घर से सुबह ऑफिस के लिए निकली तभी चोरों ने बाहर के दरवाजे का लॉक तोड़कर कर घर मे दाखिल हुए और अलमारी मे रखे सारे जेवर और नगदी लेकर चम्पत हो गये।

पीड़िता उपनिदेशक शोभा रानी श्रीवास्तव ने बताया कि जब वह घर पहुंची तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी मे रखा लगभग 30-40 लाख के जेवरात और तकरीबन 25 हजार कैश गायब था, फौरन उन्होने 100 नंबर पर सूचना दी मौके पर सीओ हजरतगंज पुलिस समेत डॉग स्क्वाड पहुंचा और जांच पड़ताल करने लगा।

वही पूरे मामले पर एसपी पूर्वी सर्वेश मिश्रा ने बताया कृषि विभाग मे तैनात शोभा श्रीवास्तव अपने घर से सुबह 10 बजे निकली थी। जब वापस लौटी तो घर का ताला टूटा था अंदर रखा सामान गायब था साथ ही बताया चोरी हुए सामान की कीमत का अभी सही पता नही चल सका है।

चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर डॉग स्क्वाड फिंगर प्रिंट टीम भी गई थी। सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं जल्द ही मामले को अनावरण कर दिया जएगा।

सवाल ये उठता है डीजीपी ऑफिस जो की हाई सेक्योरिटी जोन माना जाता है खुद प्रदेश के पुलिस मुखिया का आवास भी है वहा चोर इतनी आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं तो इससे कही ना कही राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे होती हुई दिखाई पड़ रही। पूरी घटना में हजरतगंज पुलिस के गश्त पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है।

जब राजधानी पुलिस डीजीपी मुख्यालय के आसपास के हिस्सो कों सुरक्षित नही रख सकती तो दूर दराज के इलाके के कितने सुरक्षित होगें इसक अंदाजा आसानी से लगया जा सकता है।

3 बच्चों की डूबकर मौत

लखनऊ। गोंडा के गुमड़ी घाट पर कुआनों नदी में नहाते समय तीन किशोरों की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक की हालत इलाज के बाद स्थिर है।

भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए सभी जल भरने गए थे और इससे पहले ये हादसा हो गया। हादसे से बाबागंज कस्बे में कोहराम मचा है।

धानेपुर थाना क्षेत्र के बाबागंज कस्बे के रहने वाले विजय मोदनवाल का बेटा हिमांशु (15), राधेश्याम का बेटा शेखर (14) व रेतवागाडा गांव के मजरे इमलिहवा के रहने वाले जगप्रसाद का बेटा शिवा (16) और विकास (14) अपने कई साथियों के साथ बुधवार सुबह घर से निकले।

कजरी तीज के मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सभी बच्चे जल लेने कुआनों नदी के गुमड़ी घाट पर पहुंचे। वहां जल भरने से पहले सभी नहाने के लिए नदी मे उतर गए। इसी दौरान हिमांशु, शेखर व विकास गहरे पानी मे डूबने लगे।

शिवा का कहना है कि जब

उसने अपने भाई विकास समेत अन्य बच्चों को डूबता देखा तो शोर मचाते हुए उन्हे बचाने के लिए पानी मे छलांग लगा दी लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह खुद भी पानी में डूबने लगा। सबको डूबता देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

पेट्रोल-डीजल की महंगाई के लिए भाजपा, कांग्रेस दोनों जिम्मेदार : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने पेट्रोल–डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी व महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के साथ–साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस (यूपीए) सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है।

सोमवार हुए भारत बंद को बसपा ने समर्थन नहीं दिया था। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की मायावती ने निंदा की। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस के रवैए की भी निंदा की।

मंगलवार को प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा, "पेट्रोल–डीजल के दामों में बढ़ोतरी व महंगाई के विरुद्ध हुए भारत बंद की स्थिति उत्पन्न होने के लिए हम भाजपा व कांग्रेस दोनों को ही बराबर की जिम्मेवार मानते हैं। कांग्रेस ने ही यूपीए–2 के शासनकाल में

पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया था और उसके बाद केंद्र की सत्ता में आई भाजपा सरकार भी उसी आर्थिक नीति को आगे बढ़ाती रही।

यही नहीं, भाजपा ने एक कदम और आगे निकलते हुए डीजल को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिसके चलते खेती–किसानी काफी प्रभावित हुई है।" उन्होंने कहा कि जहां डीजल–पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत से जनता परेशान है, वहीं भारतीय रुपये की कीमत भी रिकार्ड तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रही है। लेकिन जनविरोधी व अहंकारी मोदी सरकार जनता की इन परेशानियों से जरा भी विचलित नजर नहीं आ रही।

मायावती ने कहा, "भाजपा सरकार इस चुनावी वर्ष में अपने पूंजीपति व धन्नासेठ साथियों को नाराज करना नहीं चाहती, जिनके धनबल पर वह केंद्र की सत्ता में आई है और फिर आने का सपना देख रही है।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बिग टिकट रिफॉर्म यानी बड़े आर्थिक सुधार के नाम पर पूंजीपतियों व धन्नासेठों के समर्थन में और गरीब, किसान व जनविरोधी नीतियों और फैसलों को वापस लेने के मामले एक जैसे और एक ही एक ही थैली के चट्टे–बट्टे लगते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि वह पेट्रोल व डीजल के मूल्य को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि यह उसके नियंत्रण के बाहर है। इससे बसपा सहमत नहीं है।

नहीं बचेंगे जौनपुर सहित विभिन्न जिलों में हुए जबरन धर्मान्तरण के दोषी : मनीष शुक्ला

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती, धोखे से और लालच देकर धर्म–परिवर्तन कराने की जांच होगी। पत्रकारों से बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि जौनपुर में धोखे और लालच के सहारे हिन्दू परिवारों का धर्मांतरण हुआ। इस बात की भी जांच होगी कि पिछले 14–15 वर्षो से किसने दुर्गा प्रसाद यादव, कीरित रॉय और जितेंद्र सहित 271 लोगों को जौनपुर सहित चार जिलों में गरीबों और पिछड़ों को धोखा देकर, बहला–फुसलाकर और रुपयों का लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल करने की छूट दी थी। दुर्गा प्रसाद यादव और उसके कुछ साथी गांव की भोली–भाली अनपढ़ लोगों को अंधविश्वास का सहारा लेकर जानलेवा बीमारी का गलत उपचार करते थे। गंभीर बीमारी ठीक होने की झूठी गवाही लोगों से दिलवा कर धर्म परिवर्तन कराते रहे है। इसके पहले जुलाई 2014 में भी जौनपुर के नेवढ़िया में ईसाई मिशनरियों ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया था। उस समय धर्मांतरण का विरोध करने पर हिन्दू संगठन

के लोगों पर हमला भी हुआ था। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद और आश्चर्यजनक पहलू है कि पिछले सरकार में धर्मान्तरण की शिकायतकर्त्ताओं पर मुकदमें कायम होते रहे क्योंकि धर्मान्तरण कराने वालों को तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि दिसंबर 2014 में जब आगरा में मुस्लिम धर्म छोड़ कर स्वेच्छा से 17 परिवार हिन्दू बने थे। उस समय तमाम राजनीतिक दलों ने संसद के अंदर तक शोर किया था। उप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा था कि श्कुछ लोग अब प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।श जबकि उन्होने धोखे और लालच से धर्मांतरण करा रहे ईसाई संगठनों को खूली छूट और संरक्षण दे रखा था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उप्र में जब किसी दूसरे धर्म को स्वेच्छा से छोड़ कर कोई व्यक्ति या परिवार हिन्दू धर्म में शामिल होता है तो तथा कथित धर्मनिरपेक्ष विरोध शुरू कर देते है। लेकिन जब जबरदस्ती, धोखे से और लालच देकर हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यही लोग धर्म परिवर्तन का समर्थन करने लगते है।

संक्षिप्त समाचार

अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच व फिजिकल 17 से

लखनऊ। आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती–2015 के तहत शेष रह गए 1,379 पदों के लिए 17, 18 और 19 सितंबर को लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ और बरेली में जोनल मुख्यालय पर दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सीएनजी हुई महंगी

लखनऊ। डालर के मुकाबले रुपये में गिरावट के चलते गैस खरीद मूल्य में वृद्धि के कारण सीएनजी की कीमतों में 1.25 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गयी है। नई कीमतें 13 सितम्बर से प्रभावी होंगी। कल से राजधानी में सीएनजी 57.40 रुपये प्रतिकिलो मिलेगी। इससे पूर्व 30 मई को सीएनजी के मूल्य में वृद्धि की गयी थी।

घरों में मच्छर का लार्वा मिलने पर 15 को नोटिस

लखनऊ। मौसमी बीमारी के लिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर स्वास्य विभाग ने बुधवार को निरूशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, इसमें 304 मरीजों को उपचार मिला। बुखार से पीड़ित 74, डायरिया से पीड़ित 17 और 22 मरीजों के खून के नमूने लिए गये। शिविर के अलावा डाक्टरों की टीम ने घर–घर जाकर भी मरीजों का उपचार किया। मलेरिया विभाग की टीम ने कुल 213 घरों का निरीक्षण किया, इसमें 15 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी की।

अनुबंध समाप्त होने बंद हो जाएंगी महंगी जांचें

लखनऊ। बलरामपुर, सिविल अस्पताल सहित कई अन्य सरकारी अस्पतालों में कैंसर समेत ब्लड की दूसरी बड़ी महंगी जांचें तीन नवम्बर से बंद हो जाएंगी। अस्पतालों में ब्लड कलेक्शन सेंटर को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी वजह से गरीब मरीजों को विशेष जांच नही हो पाएगी। मरीजों को अब महंगी कीमत चुकाकर निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से जांच कराना पड़ेगा। यह सेंटर के बंद करने की तारीख भी तय कर दी गई है। इस बारे में लोहिया संस्थान की पैथालॉजी विभाग की प्रमुख डा. नुजहत का कहना है कि तीन नवम्बर को जांच एजेंसी के साथ करार समाप्त हो रहा है।

नाबालिगों को इंस्पेक्टर ने फटकारा

लखनऊ। पान दुकानों व गुमटियों पर पर नाबालिकों को छल्ला बनाता देख इंस्पेक्टर हजरतगंज राधारमण सिंह ने दुकानदारों के पेंच कसे। इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचे नाबालिकों को करियर के बारे में समझाते हुए गलत हरकत से दूर करने का पाठ पढ़ाया।

फैक्ट्री में अचानक फटा बश्यलर, 6 मजदूरों की मौत व दो घायल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुधवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य

शुरू किया।

बॉयलर फटने से आग लग गई। इस हादसे में छह मजदूरों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक, बिजनौर–कोतवाली देहात मार्ग पर स्थित मोहित पेपर मिल एवं केमिकल प्लांट में विस्फोट हो गया। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से यह हुई है।" उन्होंने कहा कि जहां

मृतकों में बालगोविंद, रवि, लोकेंद्र, विक्रांत, कमलबीर व चेतराम शामिल हैं। सभी कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले है।

दोनों घायल मजदूरों की हालत गंभीर है जबकि एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है।

अंतिम चरण में ऐशबाग–सीतापुर आमान परिवर्तन का कार्य

लखनऊ। ऐशबाग–सीतापुर रेलखंड का आमान परिवर्तन का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में चल रहा है। इस रेलखंड पर डेढ़ साल पहले बड़ी लाइन की ट्रेनों का संचलन शुरू हो जाना चाहिए , लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल लखनऊवासियों के लिएअच्छी खबर यह है कि दीपावली से पहले ऐशबाग–सीतापुर रेलखंड पर बड़ी लाइन की ट्रेनों का संचलन शुरू हो जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक वीके पाण्डेय ने बताया कि आमान परिवर्तन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में कभी टावर वैगन के जरिये ओएचई की तारों की जांच हो रही तो कभी इंजन व कोच पटरियों पर दौड़ाया जा रहा है। निरीक्षण के बाद जब उनकी स्वीकृति मिलेगी तभी बड़ी लाइन की इस नये रेलखंड पर ट्रेनों का संचलन हो सकेगा।

राज्य मंत्री सुरेश पासी ने किया प्रज्ञा भारत गैस का उद्घाटन

अमेठी। जिले के विकास खण्ड बाजार शुकुल के अंतर्गत रहमतगढ़ इंटर कालेज के करीब प्रज्ञा भारत गैस सर्विस एजेंसी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सुरेश पासी न किया' और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सैकड़ों लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर एवं चूल्हा वितरित किया स

मुफ्त गैस कनेक्शन वितरण उपभोक्ता सूची

समीरुल कूतूब अली, कमला पत्नी श्री राम विशाल, सिंगार कली पत्नी श्री रमेश कुमार, सुधारा पत्नी श्री रामजस, कंचन पत्नी श्रीसंजय कुमार, विमलेश पत्नी श्री दिनेश, परानपता पत्नी श्री गुरु प्रसाद, राजकुमारी पत्नी श्री रघुवीरबली, आदि उपभोक्ताओं को निशुल्क कनेक्शन दिया गया।

इस शुभ अवसर पर प्रज्ञा भारत गैस एजेंसी के संचालक प्रधान सोहन लाल पासी,डा0 बी0 आर0 अम्बेकर जन जागरण मिशन के अध्यक्ष श्री

पति मोर्या,पासी एकता मंच के संयोजक आर्मी रिटायर आर0 डी0 पासी,डा0 विजय पासी, विनोद पासी ,सियाराम पासी प्रधान (राजामऊ),भाई लाल, डा0 रमेश,राहुल पाल रामदीन गौतम,भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र शुक्ला, ब्बलू शुक्ला पत्रकार, ओंकार नाथ सिंह ,

प्रधान उदय नारायण मिश्रा, शंकर बक्स सिंह, अजय शुक्ला,ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, इत्यादि वरिष्ठ कार्यकर्ता गण इस उदघाटन समारोह में उपस्थित रहे स राज्यमंत्री सुरेश पासी ने कहा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे क्षेत्र को दो प्ज् कॉलेज की स्थापना के लिए धन आवंटित हो गया है

उसी गांव में विद्युतीकरण नहीं था पूरे गांव का विद्युतीकरण हो गया है स इस तरह से 184 विधानसभा जगदीशपुर के साथ–साथ शुकुल बाजार ब्लाक का भारी विकास हो रहा है स यह विचार व्यक्त किए राज्यमंत्री सुरेश पासी ने उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गैस वितरण करते हुए मंत्री ने कहा हमारी माताओं बहनों को चूल्हे पर खाना बनाते समय आंख खराब होने,स्वास्थ्य खराब होने का भारी खतरा था

धुएं से होने वाले प्रदूषण से फेफड़े संबंधित बीमारी का बहुत बड़ा खतरा होता है अब जब यह गैस पर खाना बनाएंगी तो इनके स्वास्थ्य के साथ–साथ इनकी आंखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा।

बिजली विभाग की पान से रंगी दीवारों की पुताई

फतेहपुर। जिले में जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर विभागों में अफरा तफरी मची हुई है वही कुछ विभाग ऐसे भी है जहाँ पर शासन का कोई डर उनको नही है। एक तरफ तो राष्ट्रीय त्योहारों में वो धूम्रपान निषेद की कसमें खाते है तो वही दूसरी ओर अपने ही आफिस और प्रांगण की दीवारों को थूकदान की दीवारों की तर्ज पर इस्तेमाल करते है।

जिले की जिलाधिकारी जहाँ एक ओर सभी गांवों और शहर के हर मुहल्ले को साफ सुथरा और सुंदर बनाए जाने की कोसिस कर रहे है वही दूसरे अधिकारी के नीचे काम कर रहे अधिकारियों की हसि उड़वाने का काम कर रहे है।

ऊपर की दिख रही तस्वीर जिले के बिजली विभाग कार्यालय की है जहाँ पर आप देख सकते है किस तरह से दीवार को थूकदान समझ कर इस्तेमाल किया जा रहा है और रँगे पुते आफिस को गन्दा कर रहे है।

कार्यालय में कमरे भही उपलब्ध है और कोई न कोई जानकारी भी अधिकारियों को समय समय पर मिलती ही रहती है पर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान अधिकारी उस ओर नही दे रहे है और न ही कोई उचित कार्यवाही ही कर रहे है।

क्या इस तरह से मोदी और योगी सरकार देश के गन्दगी को साफ कर पायेगी और इस तरह से लोगो को जागरूक करने वाले अधिकारी जब अपने ही आफिस को साफ नही रख ले रहे है।

मरीजों की सुविधा को टूटेगी ट्रामा सेंटर की दीवार

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय के ट्रामा सेंटर से शताब्दी अस्पताल जाने वाले मरीजों का स्ट्रेचर अब मेन सड़क से हो कर नहीं गुजरेगा। मरीजों को ले जाने के लिए ट्रामा और शताब्दी के बीच की दीवार को तोड़ कर नयी सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। केजीएमयू कुलपति का कार्यभार सम्हालने के बाद प्रो. एमएलबी भट्ट ने ट्रामा सेंटर से शताब्दी अस्पताल जाने वाले और वहां से आने वाले मरीजों को दिक्कत का निदान करने के लिए आश्वासन दिया था।

उन्होंने ट्रामा सेंटर और शताब्दी अस्पताल के बीच में खड़ी दीवार को तोड़ कर रास्ता बनाने का निर्देश दिया था, परन्तु यह निर्देश पूरा होने में एक वर्ष लग गया। ट्रामा सेंटर में शौचालय के बगल की दीवार को तोड़ने का काम शुरू हो गया। रास्ता आक्सीजन प्लांट के बगल से होता हुआ जाएगा। शताब्दी अस्पताल के जमीन के लेबल को ऊंचा करने का रास्ता को बनाया जा रहा है। ताकि मरीज को स्ट्रेचर से दोनों तरफ आसानी से ले जाया सकता है। रास्ता बनने के बाद मरीजों का स्ट्रेचर मेन रोड पर नहीं ले जाया जाएगा। मेन रोड पर जाने पर अक्सर चलती गाड़ियां, किनारे लगे ठेले से बचाना पड़ता था।

दस पर दहेज हत्या का मुकदमा

लखनऊ। पारा के विक्रमनगर में शीला (28) की करीब हफ्ते भर पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गयी थी। मायकेवालों को सूचना दिये बगैर ससुरालवालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसपर दोनों के बीच विवाद हुआ था। बहन ने बहनोई समेत दस पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। इंस्पेक्टर अखिलेश चन्द्र पाण्डेय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पड़ताल की जा रही है। बहन नीलम ने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को शीला की शादी राहुल निवासी विक्रमनगर से हुई थी। मायकेवालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। बावजूद ससुरालवाले आए दिन मांग कर शीला को पीटते व प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि राहुल ने परिवारवालों के साथ मिलकर हफ्ते भर पहले शीला को मार डाला।

छात्राओं ने सीखा आपदा प्रबंधन का हुनर

लखनऊ। लखनऊ के 11 वीं वाहनी एनडीआरएफ के कमाण्डेंट आलोक कुमार सिह के नेतृत्व मे 12 सदस्यी टीम ने 11 सितम्बर दिन मंगलवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरासंड सरोजनी नगर के छात्र और छात्राओं को आपदाओं व भूकंप की जानकारी देते हुए सावधानीयां बर्तने का प्रशिक्षण देकर मॉक ड्रिल कराया।

टीम कमांडर इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने छात्र– छात्राओं को भूकंप के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा व अन्य आपदाओं के दौरान सावधानियां व प्राथमिक उपचार के बारे में प्रदर्शन एवं अभ्यास के माध्यम से जानकारी दी।

महिला अस्पताल में प्रसव पीड़िता के रुपये न दिये जाने अस्पताल से भगाया

महमूदाबाद, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद कस्बा में महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिला पोलिसम उम्र 30 वर्ष पत्नी राज

नारायण निवासी ग्राम बेनीपुर पोस्ट पर्वतपुर थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।गर्भवती महिला के रक्तस्राव हों रहा था।

और धीरे धीरे महिला की हालत बिगड़ रही थी। इस लिए गांव की आशा बहु ने उसे लेकर महिला अस्पताल पहुंची।वही पर राज नारायण ने बताया कि महिला अस्पताल में मौजूद स्टाफ के द्वारा इलाज करने के लिए उससे 2 हजार रुपये मांगे गए। तो उसने 1 हजार रुपये दिये। लेकिन फिर भी नही हुआ इलाज और उसकी पत्नी को अस्पताल से बाहर कर दिया गया।

और राज नारायण रक्तस्राव से लथपथ अपनी पत्नी को रिक्शे से लेकर कोतवाली महमूदाबाद पहुंचा।कोतवाल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़िता की स्थित को देखकर उसे कस्बा इंचार्ज शत्रुधन यादव और महिला आरक्षी के साथ सी एच सी अधीक्षक के पास भेज दिया।

तो सी एच सी ने पीड़ित महिला को एम्बुलेन्स से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्साधीक्षक डॉक्टर अजय वर्मा ने कहा कि पीड़िता के पति शराब के नशे में है।

बिना डिमांड बने फ्लैटों में डूबी रकम

लखनऊ। लगभग 125 करोड़ पये की लागत से बने करीब साढ़े तीन हजार से अधिक फ्लैटों को कोई नहीं पूछ रहा है। इनको बेचने के लिए मशक्कत कर रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर पंजीकरण खोले हैं। 1500 फार्म तो बिक गए लेकिन जमा करने वालों की संख्या सौ पार भी नहीं हुई है। पहले के इंजीनियरों ने बिना डिमांड सब्रे के ही मल्टस्टोरी महंगे फ्लैटों की योजना लांच करा दी। अब एलडीए के लिए मूल धन निकालना मुश्किल हो रहा है। प्राधिकरण ने 3749 फ्लैटों की स्कीम निकाली है। इन फ्लैटों की कीमत अधिक होने से इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। इसके बाद शायद ही कभी एलडीए महंगे फ्लैटों का निर्माण करे। फ्लैटों की कीमत कम करने के बाद भी सबसे अधिक डिमांड गोमती नगर में बने फ्लैटों की है। देवपुर पाराए जानकीपुरम में बने फ्लैटों के लिए फार्म कम बिके हैं। वहीं नेहरू इन्क्लेव, वजीरगंज व अलीगंज की डिमांड सबसे अधिक है।

जाम की समस्या से निजात पाने में प्रशासन है विफल नित हो रहे प्रयोग दर प्रयोग

सुलतानपुर। नगर की यातायात व्यवस्था लाख कोशिशों के बाद भी पटरी पर नहीं आ रही हैं।

जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। सड़कों पर नित नए बढ़ते वाहन और अतिक्रमण की जस–तस स्थिति से यातायात व्यवस्था बेलगाम हो गई है।

आखिर लोग चलें कहां। वाहन सड़कों पर रेंगते हैं और घंटों जाम लगना अब आम बात हो गई है।

बढ़ती आबादी, सड़कों पर रोजाना दोपहिया और चारपहिया नए वाहनों की बढ़ती संख्या ने दशकों पुरानी सड़क पर आवागमन को पटरी से उतार दिया है। स्कूल–कॉलेज खुलने व बंद होने के समय तथा दफ्तरों से आने–जाने के घंटों में हर चौराहे और सड़क पर जाम की स्थिति अब आम हो चली है। सबसे अधिक खराब स्थिति व्यस्त सार्वजनिक स्थलों पर है। बस अड्डे के इर्दगिर्द, डाकघर चौराहा, सब्जीमंडी, बाधमंडी, दीवानी चौराहा सहित

गोलाघाट पर रोजाना जाम लगना अब आम हो चला है।

एक प्रभारी चार आरक्षी पर है जिम्मारू लगभग दस किमी क्षेत्रफल में फैले शहरी क्षेत्र में 11 प्रमुख स्थानों पर यातायात नियंत्रण की व्यवस्था होती है। प्रत्येक चौराहे पर कम से कम आठ यातायात नियंत्रण कर्मी की जरूरत होती है।

इसके सापेक्ष एक प्रभारी यातायात निरीक्षक के अधीन सिर्फ चार आरक्षी हैं। 42 होमगार्ड और 25 पीआरडी जवानो के जरिए यातायात को व्यवस्थित करने की कवायद हो रही है। दो शिफ्ट में शहर की यातायात व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। कर्मचारियों की कमी के चलते प्रातरू नौ से पांच कुछ कर्मी तो दूसरी पाली में अपराह्न एक से रात नौ बजे तक कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है।

हो रहा प्रयोग–दर–प्रयोग रू नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए

बीते दिनों से कई प्रयोग किए गए, लेकिन सब विफल रहे। बीते दिनों कुछ व्यस्त सड़कों एकल दिशा मार्ग घोषित किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही व्यवस्था धराशायी हो गई। अब दो मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर आवागमन चलाया जा रहा है,लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हो रहा है।

एआरटीओ प्रशासन से निर्देशन लेकर अवैध वाहनों की धरपकड़ की जा रही है। ई–रिक्शा का रूट सिस्टम कड़ाई से लागू कराया जाएगा। यातायात पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकरियों से अनुरोध किया गया है।

सम्पादकीय

यूपीए ने बैंकों एनपीए जाल में फंसाया

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा बैंकों के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज के संबंध में दिया गए बयान का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो सकता। इसलिए उनके बयान को कड़वा सच मानना होगा। वैसे भी उन्होंने संसद की प्राक्कलन समिति को अपना लिखिल बयान भेजा है इसलिए उसकी सच्चाई पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता है। इससे कांग्रेस और यूपीए के घटक कठघरे में खड़े हो गए हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था पर नजर रखने वालों के लिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। राजन के कहने से उन सारी बातों की पुष्टि हो जाती है जो एनपीए के संदर्भ में कही जा रहीं थी। एनपीए के बोझ से हमारी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही है और नरेन्द्र मोदी सरकार को उन्हें बचाने के लिए मोटी रकम लगानी पड़ रही है उसकी जड़ यूपीए के शासनकाल में ही निहित है। राजन ने अपने कार्यकाल में एनपीए का पता लगाने और सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका कहना है कि यूपीए के पहले कार्यकाल में पहले बड़े बैंकों ने आंख मूंदकर आधारभूत संरचना के नाम पर नियोजित परियोजनाओं को कर्ज दिया। उनकी देखा-देखी छोटे बैंकों ने देना शुरू कर दिया। परियोजनाओं की जांच तक नहीं की गई। वो परियोजनाएं उस रूप में जमीन पर नहीं उतरीं जैसी अपेक्षा थी और फिर कर्ज वापस मुश्किल हो गया। बैंकों ने कर्ज निकालने के लिए कंपनियों को और कर्ज दिए और यह बढ़ता चला गया। उनका मानना है कि बैंक अधिकारियों के अति उत्साह, सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुस्ती और आर्थिक वृद्धि दर में नरमी डूबे कर्ज के बढ़ने की प्रमुख वजह है। बैंकों का उत्साह तो साफ दिखता है किंतु इसका कारण क्या हो सकता है यह जानने की जरूरत है। क्या सरकार की ओर से बैंकों को इसके लिए संकेत दिए जाते थे? बैंक अपनी जोखिम इतने सारे कर्ज दे देंगे यह सामान्य समझ से परे है। इसमें बैंक अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी होगा। आरोप यह भी है कि बैंक अधिकारियों द्वारा कर्ज की याद दिलाए जाने पर उन्हें धमकी तक मिलती थी। ऐसा वातावरण क्यों बन गया था इसकी तो जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के यह कहने से उसका दोष कम नहीं हो जाता कि हम जब गए तो एनपीए केवल दो लाख करोड़ था और आज नौ लाख करोड़ हो गया। यह इसलिए हो गया कि वर्तमान सरकार ने पूरे एनपीए को सामने लाने की कोशिश की है ताकि बैंकिंग पण्राली की स्थिति समझी जा सके।

न्यूनतम जनतांत्रिक सिद्धांत पर खतरा

भाजपा 2019 के आम चुनाव के लिए और जाहिर है कि इस साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना समेत पांच राज्यों के विधानसभाई चुनाव के लिए अपने नये नारे चाहे अभी आजमा ही रही हो पर उसने अगले चुनाव के लिए अपना चेहरा ही नहीं बल्कि अपना इकलौता नेता पक्के तौर पर खोज लिया है। यह संयोग नहीं है कि ''अजेय भारत, अटल भाजपा' का इस पार्टी का नया नारा भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई-दिल्ली में हुई दो-दिनी बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन में ही दिया गया। हालांकि शुरू में प्रस्तावित नारे के मुकाबले भाजपा की ''अजेयता' घोषणा करने में अंततः संकोच किया गया लेकिन इसका यह अर्थ हरगिज नहीं है कि भाजपा की बैठक में कोई कम अहंकार देखने को मिला। यह अहंकार इस तरह की शेखी तक भी जाता है कि 2019 का चुनाव तो भाजपा जीतेगी ही जीतेगी और 2014 के चुनाव से भी बड़े बहुमत से जीतेगी। और उसने 2019 का चुनाव जीत लिया तो पचास साल तक कोई उसे हिला नहीं पाएगा।

वास्तव में मोदी-शाह के नेतृत्व में भाजपा ने ऐसी शेखी मारने तथा हवाई दावे करने को अपने प्रचार का प्रमुख हथियार बना लिया है। सत्ताधारी पार्टी गोयबल्स की सुयोग्य शिष्य नजर आती है। जाहिर है कि इस तरह के दावे यही मानकर किए जाते हैं कि नासमझ जनता को तो कुछ भी समझाया जा सकता है। इसीलिए हालांकि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक एक के बाद एक सभी महत्त्वपूर्ण चुनावों में नतीजों के जरिए जनता ने अमित शाह के अतिरंजित दावों को स्पष्ट नकारा है, इसके बावजूद भाजपा अध्यक्ष को बार-बार ऐसे दावे करने में कोई संकोच नहीं होता। वह तो बेधड़क उत्तर प्रदेश में भी

पिछली बार की 72 से दो सीट फालतू जीतने के दावे करते फिरते हैं, जबकि सचाई यह है कि इस राज्य में उपचुनाव में लोक सभा की तीन में से तीनों सीटें हारकर भाजपा सीटों के पिछली बार के आंकड़े में तीन की कमी पहले ही कर चुकी है। लेकिन भाजपा खुद अपनी दपरेक्तियों की पोल खोल देती है, जब मोदी-शाह की जोड़ी पूरा ध्यान विपक्ष पर निराधार हमले करने में लगाए नजर आती है। 2014 से भी बड़े बहुमत से जीतने, नौ करोड़ कार्यकर्ताओं तथा योजनाओं के लाभों के सहारे तेतीस-चौंतीस करोड़ मतदाताओं को अपने पीछे लेने, मोदी की लोकप्रियता रेटिंग चार साल बाद भी 70 फीसद से ऊपर बनी रहने, कांग्रेस के शासन के 48 साल का मुकाबला मोदी के राज के 48 महीने से करने आदि की तमाम डींगें हांकने के बावजूद पूरी बैठक की चर्चा यही दिखाने पर केंद्रित थी कि विपक्ष के पास कोई ''नेता, नीति और नीयत ही नहीं है'। वह तो सिर्फ मोदी को ''रोकना' चाहता है! दिलचस्प यह कि हालांकि अमित शाह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ही विपक्षी एकता के प्रयासों को भाजपा के हिसाब से बिल्कुल बेमानी करार देकर खारिज कर दिया था, इसके बावजूद मोदी ने बैठक के दूसरे दिन के अपने संबोधन में ज्यादा समय विपक्षी गठबंधन के विचार पर हमला करने में ही लगाया। आखिर, क्यों? इसलिए कि मोदी-शाह जोड़ी बखूबी जानती है कि अगले चुनाव की तो बात ही क्या करना, 2014 के आम चुनाव में भाजपा की प्रकटतः ''जबर्दस्त जीत' भी एक-तिहाई से कम वोट पर टिकी हुई थी यानी दो-तिहाई वोट भाजपा के खिलाफ पड़े थे। इस वोट का एक हद तक एकजुट होना भी, मोदी के राज के खिलाफ जनता के सभी हिस्सों के बीच तेजी से बढ़ते असंतोष के साथ जुड़कर, आसानी से चुनाव की बाजी पलट सकता है। इसीलिए सारी शेखी के बावजूद मोदी-शाह की जोड़ी विपक्ष को एकजुट करने के प्रयासों पर हमले करने, उन्हें अनैतिक बताकर बदनाम करने पर ही अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाती है। इस क्रम में भाजपा बार-बार अपने तानाशाही मिजाज के सबूत देती है। ऐसा ही एक और सबूत पेश करते हुए भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में संसद के पिछले सत्र में आए अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार के बचे रह जाने का ढोल ही नहीं पीटा गया, बल्कि विपक्ष के मोदी सरकार के खिलाफ अविस प्रस्ताव रखने पर ही हमला किया गया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हिसाब से तो विपक्ष के पास बहुमत न होने के बावजूद, अविस प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार किया जाना ही, विपक्ष के प्रति मोदी सरकार की भारी ''उदारता' का सबूत था! लेकिन भाजपा से, जो मोदी सरकार के हर तरह के विरोध को ही ''अपराध' बना देने पर तुली हुई है, ऐसे तानाशाहीपूर्ण रुख के सिवा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी विास रखने वाला व्यक्ति जानता है कि अविास प्रस्ताव सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने का सर्वस्वीकार्य और आम-फहम हथियार है। लेकिन यह एक सुप्रीमो की अंध-भक्ति से संचालित जनतंत्र-विरोधी मिजाज का मामला है। दिलचस्प है कि अमित शाह ने खुद ही यह कहकर नरेन्द्र मोदी को अपनी पार्टी के निरंकुश नेता के आसन पर बैठा दिया कि पूर्व-प्रधानमंत्री, ''मनमोहन सिंह पार्टी के पीछे चलते थे, मोदी के पीछे पार्टी चलती है।' याद रहे कि भाजपा, जो वैसे भी इस अर्थ में एक सामान्य जनतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, तो अंततरू बाहर से आरएसएस से संचालित पार्टी है। उस संघ से जो एक नेता के सिद्धांत पर चलता है। बहरहाल, वह अब तो न्यूनतम जनतांत्रिक सिद्धांत पर ही हमला करती नजर आती है कि अपने सदस्य समूह की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बड़े से बड़े नेता से भी ऊपर होती है, और होनी भी चाहिए। अचरज नहीं कि ऐसी पार्टी के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय की बैठक में पेट्रोल के दिनों-दिन बढ़ते दाम, रुपये के दिन पर दिन गिरते दाम आदि से लेकर तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, भीड़ हत्याओं, अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ते हमलों, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों तक, सरकार और देश के सामने खड़ी किसी भी चुनौती पर विचार तक करने की जरूरत नहीं समझी गई।

भारत बंद से हासिल क्या हुआ

इसकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस की ओर से आहूत भारत बंद का कितनी पार्टी का समर्थन मिला? महत्त्वपूर्ण यह है कि किन पार्टियों का समर्थन नहीं मिला। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि इस भारत बंद से हासिल क्या हुआ? जो हासिल होगा क्या वह बंद के बिना नहीं हो सकता था? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते मूल्यों के खिलाफ यह बंद था। कोई भी समझ सकता है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक था। कांग्रेस एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका में ही दिखना नहीं चाहती, धीरे-धीरे नरेन्द्र मोदी और भाजपा विरोधी राजनीति की धुरी बनने की रणनीति पर भी काम कर रही है। उसे मालूम है कि मूल्य में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकना सरकार के वश में नहीं। अगर थोड़ा शुल्क घटा दिया जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एवं देश की वित्तीय व्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर होगा। अगर केंद्र सरकार अपने उत्पाद शुल्क में थोड़ी कटौती करती है तो भी यह इसलिए नहीं कि वह बंद से डर गई है या दबाव में आ गई है। इस समय पेट्रो पदार्थो का मूल्य बढ़ना देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

सरकार के लिए राजनीतिक रूप से यह जोखिम भरा है।

वस्तुतः कांग्रेस या विपक्षी दलों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए भारत बंद करना जरूरी नहीं था। इससे देश का नुकसान होता है। कांग्रेस ने अन्य दलों से राय लिये बगैर बंद आयोजित कर दिया, इसलिए विपक्षी एकता की जगह बिखराव का संदेश ज्यादा गया। ममता ने मूल्य बढ़ने के विरोध को सही बताते हुए बंद को गलत बताया, बीजद ने अपने को अलग रखा, सपा और बसपा का कोई नेता राहुल के साथ मंच पर नहीं आए..आम आदमी पार्टी ने बंद का समर्थन नहीं करने की घोषणा की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता राहुल के मंच पर गए। भाजपा इससे यकीनन प्रसन्न होगी कि चलो सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं आ सकी। कांग्रेस यदि सबसे राय विचार कर सरकार विरोध का कार्यक्रम बनाती तो हो सकता है उसमें भारत बंद का निर्णय नहीं होता, मगर सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिख सकता था। राजनीतिक लाभ-हानि से अलग विचार करने की जरूरत है कि आखिर भारत बंद करके कोई दल या समूह क्या लक्ष्य हासिल करता है?

बढ़ते ईंधन मूल्यों से कब मिलेगी राहत?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग से आम आदमी बुरी तरह से झुलस रहा है। इसकी तपिश से कब तक राहत मिल पाएगी, इसके अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार की बार-बार एक ही दलील है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश में तेल की मांग को पूरा करने के लिए इसका 80 फीसद आयात किया जाता है, जिसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। जाहिर है कि कच्चे तेल का आयात महंगा पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता महंगाई की इस मार को कब तक झेल पाएगी? एक बारगी पेट्रोल के बारे में जरूर कहा जा सकता है कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल मध्यम वर्ग ही करता है, लेकिन डीजल एक ऐसा ईंधन है, जिसका खेती और सार्वजनिक परिवहन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।

जाहिर है कि इसकी महंगाई का असर गरीब से गरीब आदमी पर भी पड़ता है। इसके बोझ के दबाव में आम आदमी की आह निकल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी आवाज सरकार के

कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि ऐसा न होता तो कुछ न कुछ राहत के उपाय जरूर किए जाते। सरकार भले ही दावा करे कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब बाजार के हवाले हैं, जिसकी दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि इनकी कीमतें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां ही निर्धारित कर रही हैं, जिसका मालिकाना हक सरकार के पास है। क्या सरकार का इन कंपनियों में वाकई कोई दखल नहीं है? इस बात पर शायद ही कोई भरोसा करे। यह भी हकीकत है कि तेल शोधन के कारोबार से जुड़ी कंपनियां लगातार मोटा मुनाफा कमा रही हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी इंडियन ऑयल ने पिछले वित्त वर्ष 21,346 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 7000 करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। यदि सरकार तेल कंपनियों को मुनाफा मार्जिन में कटौती के लिए राजी कर ले और पेट्रोल-डीजल पर वसूले जा रहे भारी-भरकम करों में कुछ कमी करने की पहल करे तो इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है।

हाल समुदाय द्वारा इस्लाम का चीनीकरण

इस्लामी पाकिस्तान की जानकारी में (बल्कि उसकी मूक स्वीकृति से) कम्युनिस्ट चीन अपने पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में मुसलमानों का चीनीकरण कर रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक (11 अगस्त, 2018) में अपनी जांच रपट पेश करते हुए गेई मैकडूगल ने बताया कि बीस लाख मुसलमानों को माओवादी शिक्षण शिविरों में अनीश्वरवादी बनाने के लिए कैद में रखा गया है। दस लाख सुन्नियों को जेल में नजरबंद कर दिया गया है। क्या अपराध है इन लोगों? इन लोगों का अपराध सिर्फ यही है कि ये अपनी जीवन पद्धति इस्लामी आचरण के मुताबिक संवारना चाहते हैं।

शिंजियांग के मुसलमानों के उत्पीड़न पर विभिन्न इस्लामी राष्ट्र, खासकर सऊदी अरब, की खामोशी यही दर्शाती है कि चीन से तिजारत का महत्त्व इस्लामी अकीदे से ऊपर है। चीन के बहुसंख्यक उन्हें मिटा देना चाहते हैं। उइगर मुस्लिम युवतियों की शादी जबरन हान युवकों से कराई जा रही है। तुर्की भाषा की जगह चीनी मंडारिन को अनिवार्य भाषा कर दिया गया है, और उनके मजहबी दस्तूर और रिवायतों पर पाबंदी लगाई जा रही है

बर्लिन के प्रोफेसर हांस-क्रिश्चिन गुंथर ने चीन से लौट कर (26 अगस्त, 2018) को अपने मीडिया कॉलम में यह लिखा कि उइगर-भाषी मुसलमानों के दमन से भारत का सीधा सरोकार होना चाहिए क्योंकि यह चीन की विदेश नीति का खास आधार बन चुका है। शिंजियांग के मुसलमानों के उत्पीड़न पर विभिन्न इस्लामी राष्ट्र, खासकर सऊदी अरब, की खामोशी यही दर्शाती है कि चीन से तिजारत का महत्त्व इस्लामी अकीदे से ऊपर है, अधिक है। सवा सौ करोड़ की हान नस्ल के चीनीजन के सामने दो प्रतिशत उइगर मुसलमान तो जीरे के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन वे चीन के लिए सरदर्द से कम नहीं समझे जा रहे। उनके विरोधी तेवर और स्वर के कारण चीन के बहुसंख्यक उन्हें हर हाल में मिटा देना चाहते हैं। इसके लिए तीन तरीके अपनाए गए हैं। उइगर मुस्लिम युवतियों की शादी जबरन हान युवकों से कराई जा रही है। तुर्की भाषा की जगह चीनी मंडारिन को अनिवार्य भाषा कर दिया गया है, और उनके मजहबी दस्तूर और रिवायतों पर पाबंदी लगाई जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से 1949 में झिनझियांग में 95 प्रतिशत उइगर मुसलमान और पांच प्रतिशत हान चीनी थे। आज की तारीख में दोनों पचास फीसद अर्थात् ठीक बराबर हो गए हैं।

आखिर, कम्युनिस्ट चीन की केंद्रीय सरकार से इन उइगर मुसलमानों ने मांगा क्या था? बस वे अधिकार, जिनका भारत में हर मुसलमान दशकों से निर्बाध रूप से उपभोग कर रहा है, चाहते हैं। उइगर चाहते हैं रू उन्हें जुम्मे की नमाज मस्जिदों में अदा करने दी जाए, वजू करने के लिए नल का पानी वहां पर मिले। हज यात्रियों की संख्या में की गई कटौती खत्म हो। पचास वर्ष से कम आयु वालों को हज पर जाने की इजाजत वापस दी जाए, अठारह वर्ष से कम उम्र वालों को मस्जिद प्रवेश की अनुमति दी जाए। उनकी मातृ भाषा तुर्की को सीखने पर लगी पाबंदी हटा ली जाए और उन पर मंडारिन भाषा कतई न लादी जाए।

उइगर साहित्य को अरबी लिपि में ही रहने दिया जाए, मजहबी किताबों की बिक्री पर से पाबंदी उठा ली जाए, पाक कुरान पर सरकारी संस्करण न थोपा जाए, मदरसों की सील खोल दी जाएं, पुर्नशिक्षित करने के नाम पर बंदी शिविरों में अकीदतमंदों को जबरन नास्तिक न बनाया जाए। इसके साथ ही, सरकारी दफ्तरों में नमाज पढ़ने के लिए अल्पावकाश का प्रावधान किया जाए। उनकी रिहायशी बस्तियों में घेंटी का गोश्त न बेचा जाए। उनके अपने रोजगार में बहुसंख्यक हान वर्ण के चीनीजन को वरीयता न दी जाए। उनकी ऐतिहासिक राजधानी कासगर को विश्व धरोहर करार दिया जाए। उनकी ये मांग भी हैं कि ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त कर आवासीय कॉलोनी और शॉपिंग माल नहीं बनाए जाएं। उइगर मुसलमान उदार सूफी चिंतन से प्रभावित हैं। उनकी स्वाधीनता, विकास तथा समरसता वाली आकांक्षा को आतंकवाद कहना तयों को विकृत करना होगा। उइगर मुसलमान उज्बेकियों के निकट हैं, जबकि तालिबानी लोग पश्तून हैं। दोनों परस्पर शत्रु हैं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जब कोई उइगर मुसलमान किसी फिदायीन हमले का दोषी पाया गया हो। लेकिन चीन ने इन उइगर मुसलमानों पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा दिया है। लेकिन कोई व्यंग्यात्मक लेख छप जाए, चेचेन्या और कोसोवो के राष्ट्र विरोधियों पर पुलिसिया कार्रवाई हो या ऐसी ही कोई बात हो तो भारतीय मुसलमान उससे अपना सीधा सरोकार जोड़ लेते हैं। हाल ही में हजारों मील दूर बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान असम में घुस रहे थे, तो भारतीय सुरक्षा बलों से उनका टकराव हुआ। इस पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुसलमान हजरतगंज और वीटी स्टेशन तक बल्लम, बर्छी, छूरी, लाठी, जंजीर आदि लेकर उत्पात मचाने लगे, पुलिस असहाय थी। मगर इन्हीं मुसलमानों ने आज तक शिंगजियांग के पीड़ित सधर्मियों के समर्थन में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग और चीनी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन नहीं किया। उसकी दुहरी नजर में जमात-उद-दावा, जो लश्कर का सियासी अंग है और भारत में कई वारदात को अंजाम दे चुका है, एक स्वयंसेवी संस्था है, जो मिल्लत की खिदमत करता है।

इसलिए सवाल यह है कि हिन्दू-बहुल भारत में फल फूल रहे इस्लामी तंजीमों, अंजुमनों, संगतों तथा रफाकतों ने शिंगजियांग के सुन्नियों के प्रति एकजुटता और हमदर्दी कितनी और कब दिखाई? कश्मीरी गिलगिट से शिंगजियांग की राजधानी कासगर की दूरी सवा सौ किलोमीटर के करीब है। काराकोरम मार्ग से पुराने रेशम मार्ग होते हुए वहां पुहंचा जा सकता है। यह इलाका भारतीय सीमा के समीप है। किंतु यह प्रश्न इसलिए खटास भरा हो जाता है क्योंकि विश्व में कहीं भी मुसलमानों पर हमला होता है, तो भारत के मुसलमान तुरंत सड़क पर उतर आते हैं। इस्रयल की अलअक्सा मस्जिद में तोड़फोड़ हो, डेनमार्क के अखबार में कोई काटरून बना दे, पेरिस के दैनिक अखबार में

शिंगजियांग के पीड़ित सधर्मियों के समर्थन में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग और चीनी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? देवबंदी, बरेलवी, जमाते इस्लामी, असदुद्दीन ओवैसी, नदवा कॉलेज (लखनऊ), दानीश्वरों, अदीबों, अकीदतमंदों को इसका जवाब देना होगा। भारत सेक्युलर है, और यहां मजहबी सियासत करना गुनाह है। यदि इन लोगों को यह सेक्युलर कानून गंवारा नहीं है, तो ये दारुल इस्लाम को तलाश लें। दारुल हर्ब को छोड़ दें क्योंकि सत्तर साल हो गए, भारत मजहब के कारण पिछड़ता गया। नई पंथनिरपेक्ष पीढ़ी के बर्दाश्त के यह बाहर हो गया है।

भारत के भरोसे को कम करता नेपाल

नेपाल ने पुणे में चल रहे ''बिम्सटेक' देशों के पहले संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास के लिए अपनी फौज भेजने से इनकार करके कूटनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया है। पिछले महीने ही नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस क्षेत्रीय समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसमें भाग लेते हुए संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद की चुनौती से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाना है। समूह के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हो गया है कि नेपाल को इसका बहिष्कार करना पड़ा। जाहिर है, नेपाल के इस कदम ने भारत समेत इस क्षेत्रीय समूह को दुविधाजनक स्थिति में डाल दिया है। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि नेपाल ने बिम्सटेक के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। नेपाल की ओर से दी गई सफाई भी कम हास्यास्पद नहीं है।

कहा गया है कि विरोधी दलों और मीडिया के विरोधी रुख के कारण यह फैसला लेना पड़ा। दरअसल, सचाई यह है कि इस क्षेत्रीय समूह के बीच सुरक्षा और प्रतिरक्षा सहयोग बढ़ाने के भारतीय प्रस्ताव से नेपाल का वर्तमान नेतृत्व सहमत नहीं है। सच यह भी है कि नेपाली प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली दो हजार पंद्रह की आर्थिक नाकेबंदी की घटना से अब तक उबर नहीं पाए हैं। ओली इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को जिम्मेदार मानते रहे हैं। नेपाल का चीन के करीब जाने के पीछे आर्थिक नाकेबंदी की निर्णायक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ध्यान रखने वाली बात है कि नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी के समय ओली वहां के प्रधानमंत्री थे। अभी पिछले दिनों ही चीन ने नेपाल की वस्तुओं की आवाजाही के लिएअपने चार बंदरगाह खोल दिए हैं। जाहिर है कि चीनी बंदरगाहों की सुविधा मिलने के बाद नेपाल की भारत पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन नेपाली नेतृत्व को ध्यान रखना चाहिए कि चीन और नेपाल की भौगोलिक दूरी एक बड़ा मुद्दा है।

उत्पीड़न के खिलाफ शुरूआती विरोध `मौन'

मनीषा सिंह

किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ पहला चीत्कार अक्सर मौन की भाषा में फूटता है। यह शुरु आती विरोध होता है जो नादान उम्र के तकाजों और अपने अधिकारों के अज्ञान के कारण इतना मुखर नहीं हो पाता कि मदद के लिए बनी किसी हेल्पलाइन पर अपनी पीड़ा बता सके और अत्याचारों की कोठरी से खुद को बाहर निकालने की आवाज उठा सके। हालांकि पढ़ा जा सकता तो इन घुटी-छिपी आवाजों के पीछे का दर्द समझ में आता और शायद तब उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की मदद का भी कोई जरिया बन पाता। यह मामला असल में पिछले तीन वर्षो में देश की पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन पर मिलीं एक करोड़ 36 लाख खामोश फोन कॉल्स का है, जिनके पीछे शायद कोई बच्चा मौजूद था, लेकिन उत्पीड़क के भय के चलते पुलिस को फोन मिलाने के बावजूद अपनी बेबसी बयान नहीं कर पाया। इन फोन कॉल्स का खुलासा हाल में हरलीन वालिया चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन ने किया है। इसके मुताबिक बीते तीन सालों में, अप्रैल, 2015 से मार्च, 2018 के बीच, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर पूरे देश में 3. 4 करोड़ फोन कॉल्स मिलीं। इनसे दिखता है कि इधर के वर्षो में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुंह खोलने का कुछ तो साहस लोगों में आया है। पर इस जानकारी का एक सिरा अभी भी बेहद चिंताजनक है। वह यह कि थानों में इस हेल्पलाइन से जुड़े फोन की घंटी बजने पर जब उन्हें उठाया गया तो उनमें से 1 करोड़ 36 लाख कॉल्स में दूसरी तरफ से बिजली का पंखा चलने या कपड़ों की सरसराहट की आवाजें ही आई। पिछले कुछ अरसे में बिहार और यूपी के बाल संरक्षण गृहों की कलई खुलने के संदर्भ में देखें तो कहा जा सकता है कि ऐसी खामोश टेलीफोन कॉल करने वालों बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा। किसी अत्याचार के हद से गुजरने के बाद ही उन्होंने किसी तरह जानकारी जुटाकर चाइल्ड हेल्पलाइन का नम्बर हासिल किया होगा। कहीं से मोबाइल फोन आदि जुटाकर मदद के लिए फोन किया होगा। लेकिन पीड़क का चेहरा सामने आने पर उन बच्चों का साहस जवाब दे गया होगा और वे ऐन मौके पर खामोश रह गए होंगे। निस्संदेह ये आशंकाएं फाउंडेशन के शोध और समाज की अपनी समझ पर आधारित हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ जैसे घृणित हादसे होते देख रहे हैं, उनके मद्देनजर इन आशंकाओं को खारिज करना आसान नहीं है। अनाथ बच्चों, माता-पिता में संबंध विच्छेद की स्थितियों और जीवन निर्वाह के लिए मां का किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर हो जाना या फिर बाल संरक्षण गृहों में मौजूद बच्चों को कैसी यातनाएं इधर झेलनी पड़ी हैं, उनके असंख्य विवरण हमारे सामने मौजूद हैं।

बच्चों में भी लड़कियों पर अत्याचार की घटनाओं ने तो सारी हदें ही पार कर ली हैं। उन्हें किसी अनजान, पड़ोसी या अपराधी के हाथों ही यातना नहीं झेलनी पड़ रहीं, बल्कि नजदीकी रिश्तेदारों तक से यौन उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। हो सकता है कि फोन के दूसरे सिरे पर मौजूद बच्चियों ने ऐसे ही किसी शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ जाने का साहस किया हो लेकिन या तो थाने से मिले प्रत्युत्तर ने उन्हें फौरन ही खामोश कर दिया होगा या फिर उत्पीड़क की कोई चेतावनी उनके कानों में उस वक्त गूंज गई होगी।यूं हेल्पलाइन संभालने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे फोन आने पर दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति को धीरज से अपनी बात निस्संकोच कहने का साहस दें।

'सुप्रीम कोर्ट हमारा है' वाले बयान से मुकरे मुकुट बिहारी, कहा- गलत तरीके से पेश की मेरी बात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए अपने बयान पर अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कभी सुप्रीम कोर्ट को अपना नहीं बताया और बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अपने पहले बयान से मुकरते हुए मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कभी अपना नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट सभी का है और मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया गया।

बीजेपी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने बहराइच पहुंचे योगी सरकार के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा था, श्मैंने यह कभी नही कहा कि बीजेपी मंदिर मुद्दे पर आई है, बीजेपी विकास के मुद्दे पर आई है, लेकिन मंदिर हमारा आराध्य है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनने को लेकर हम कृत संकल्प है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है न्यायपालिका भी हमारी है कार्यपालिका भी हमारी है।

यह बातें उन्होंने डाक बंगले में पत्रकारों को संबोधित करते हुई कही थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है और आम लोगों के साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी बीजेपी से पूछ रही है कि राम मंदिर कब बनेगा।

आपको यहां बता दें कि अयोध्या जमीन विवाद पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है।

बिजनौर में हुए केमिकल हादसे को लेकर योगी दुःखी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में बुधवार की सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से मारे गये श्रमिकों के प्रति दुःख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में मारे गये श्रमिकों के परिजनों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि बिजनौर से करीब आठ किमी दूर नगीना रोड पर स्थिम मोहित पेट्रो केमिकल फैक्ट्री में सुबह करीब सात बजे वैल्डिंग करते समय सिलेंडर फट गया था जिसकी चपेट में आकर छह मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये।सिलेंडर

फटने के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गयी जिसे आसपास के लोगों और मजदूरों ने कडी मशक्कत के साथ नियंत्रण कर लिया। इस घटना के बाद फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर लापता बताया जा रहा है।

लापरवाही करने पर वेतन रोकने की चेतावनी

बदायूँ। राज्य स्तरीय टीमों के मार्गदर्शन में कार्यरत 04 जिला स्तरीय व 42 ब्लाक स्तरीय टीमों द्वारा बुखार के कुल 4603 रोगियों को उपचार एवं जांच की गई तथा आर0डी0टी0 किट द्वारा 91 पी0वी0 व 67 पी0एफ0 रोगी चिन्हित किये गये, जिनका आर0टी0 एवं ए0सी0टी0 उपचार किया गया।

मलेरिया विभाग द्वारा 13 टीमें गठित कर 09 ग्रामों मे लार्वीसाइडल छिड़काव (तिगुलापुर, सेमरिया, छजऊ, बीरमपुर, इस्माईलपुर, गिधौल, छोटा व बड़ा परसुरा, मौजमपुर), 1 ग्राम के 285 घरां में पायरेथ्रम स्प्रे तथा 09 ग्रामों मे फॉगिंग कराई गई। प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल हेतु क्लोरीन गोलियों के उपयोग का तरीका बताते हुये वितरण किया जा रहा है तथा ओ0आर0एस0 पैकिट वितरित किये गये। सभी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारीध्स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्षेत्रों का भ्रमण कर बुखार व मच्छरों से बचाव के सम्बन्ध में ''क्या करें? क्या न करें?'' के सम्बन्ध में पम्पलैट्स वितरण तथा माईकिंग के माध्यम से जनमानस को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर रहें है तथा प्रभावित क्षेत्रों मे आशा, ए0एन0एम0 द्वारा क्षेत्रों का सघन भ्रमण कर बुखार के रोगियों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला चिकित्सालयों व सभी सामु0ध्प्रा0स्वा0केन्द्रों पर फीवर हैल्प डैस्कध्फीवर क्लीनिक की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें बुखार के कुल 2765 रोगियों को उपचारित किया गया तथा 1037 रक्त पट्टिकाये व 1247 आर0डी0टी0 किटों से जांच कराई गई, जिसें कुल 75 पी0वी0 व 03 पी0एफ0 को चिहिन्त हुये।

जिला संक्रामक रोग नियन्त्रण टीम के दो चिकित्सकों डा0जौन सिंह व डा0सोहेल खान पर कार्य में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में वेतन रोककर चेतावनी पत्र जारी कर दिया गया है तथा जिन सामु0ध्प्रा0स्वा0केन्द्रों पर सभी बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड्स नही बनायी जा रही है, उनको चेतावती पत्र जारी कर दिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

लखीमपुर में मिला स्वाइन फ्लू का मरीज, हालत गंभीर

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय के गांधी वार्ड में लखीमपुर के स्वाइन फ्लू का मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। मरीज को आक्सीजन लगा दिया गया है और विशेषज्ञ डाक्टर उस पर निगरानी कर रहे है। उधर स्वास्य महानिदेशालय ने प्रदेश में पहला स्वाइन फ्लू मरीज की पुष्टि होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया है। खासकर एयरपोर्ट को विशेषतौर पर संदिग्ध मरीजों की जांच करने के लिए निर्देश दिये जा रहे है। लखीमपुर निवासी मो. आतिफ कु छ दिन पहले केजीएमयू में स्वाइन फ्लू की जांच रिपोर्ट पाजिटिव लेकर आया था।

गोसाईगंज में विवाहिता की हत्या

गोसाईगंज-लखनऊ। मोहनलालगंज स्थित रंजीतखेड़ा गांव निवासी सतीपाल की बेटी कोमल रावत (23) की शादी वर्ष 2016 में गोसाईगंज के सिटकिहा कला के रहने वाले रामसेवक के बेटे शिवा से हुई थी। शिवा मजदूर है। दम्पत्ति के एक साल का बेटा है। पिता सतीपाल का आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद से ही दामाद शिवा व उसके घरवाले दहेज में कोमल से मायकेवालों से मोटरसाइकिल मांगने को कहने लगे। कोमल ने ससुरालवालों की मांग के बारे में मायकेवालों को बताया था। आरोप है कि मंगलवार शाम दामाद शिवा ने कोमल को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गयी। हत्या के बाद शिवा व उसके घरवालों ने बिना मायकेवालों को सूचना दिये बुधवार सुबह शव का अंतिम संस्कारकर दिया। अंतिम संस्कार के बाद पिता सतीपाल को बेटी कोमल की मौत की सूचना हुई। पुलिस ने सतीपाल की तहरीर पर दामाद शिवा, उसके पिता रामसेवक व बड़े भाई के खिलाफ दहेज हत्या व साक्ष्य छिपाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।

मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

लखनऊ। बख्शी का तालाब पुलिस ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपित नरेश वर्मा को बुधवार को अचरामऊ मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय दलित मंदबुद्धि युवती परिवार के साथ रहती है। बीते शुक्रवार को नरेश ने मौका देख युवती से दुष्कर्म किया था। घर पहुंचने पर युवती की हालत देख घरवालों ने पूछा तो उसने आपबीती बतायी। पीड़िता की मां ने अगले दिन बीकेटी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुष्कर्म व एससीध्एसटी एक्ट की नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया था।

तमंचे बरामद, युवक गिरफ्तार

लखनऊ। पीजीआई पुलिस ने बुधवार को गश्त के दौरान शनि मंदिर तेलीबाग के पास से शातिर बदमाश कल्लू नट निवासी कुम्हारमण्डी तेलीबाग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 12 बोर का तमंचा व दो कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपित कल्लू के खिलाफ आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

'सुविधा पटल' का एसएसपी ने लिया जायजा

लखनऊ। एसएसपी के तमाम निर्देशों के बाद भी राजधानी पुलिस फरियादियों की शिकायतों को नहीं सुन रही है। मंगलवार को एसएसपी द्वारा पुलिस आफिस में गठित एक सिंगल विंडो ''सुविधा पटल' का आलम चौबीस घण्टे बाद ही बदल गया। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भ्रमण के दौरान सुविधा पटल का जायजा लिया। कर्मचारियों की अनुपस्थिति व कार्यपप्राली से खफा एसएसपी ने जन शिकायत प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं। इस दौरान एसएसपी ने सिपाही की कुर्सी पर बैठकर पीड़ितों की शिकायतें सुनने के बाद उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया।बुधवार को एसएसपी कलानिधि नैथानी एक बार फिर पुलिस आफिस में भ्रमण के लिए पहुंच गये। एसएसपी के आने की सूचना फैली तो पुलिस आफिस में हड़कम्प मच गया। भ्रमण के दौरान एसएसपी सीधे जन सुनवाई हेल्प डेस्क ''सुविधा पटल' पर पहुंचे। वहां का आलम देख एसएसपी का पारा चढ़ गया। सुविधा पटल में सिपाही की कुर्सी पर बैठकर एसएसपी ने अनुपस्थित पुलिस कर्मचारियों को देख जन शिकायत प्रभारी को फटकारा।फरियादियों को बैठा देख एसएसपी ने पहले उनकी पीड़ा सुनी और फिर उसे दूर करने का आश्वासन दिया। एसएसपी ने कार्यपप्राली से लेकर संबंधित जन शिकायत प्रभारी के विरूद्ध जांच के आदेश दे दिये। उन्होंने वहीं पर बैठकर सीओ कार्यालय के कर्मचारियों को जनता की शिकायत सुनने व उन्हें दूर करने का पाठ पढ़ाया। एसएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जन सुनवायी में लापरवाही मिलेगी तो वे कार्रवाई करेंगे।

पूर्व विधायक समेत तीन के खाते से उड़ाए 1.42 लाख

लखनऊ। गोमतीनगर में पूर्व विधायक के एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर जालसाज ने 47 हजार रुपये पार कर दिये। वहीं, विकासनगर में बैंक अधिकारी बनकर जालसाज ने महिला के खाते से 49 हजार रुपये उड़ा लिए। उधर, पीजीआई में रहने वाले रिटार्यड सैन्य अधिकारी का पर्स सड़क पर कहीं गिरकर खो गया। पर्स में रखे एटीएम कार्ड की मदद से जालसाज ने 46 हजार रुपये निकाल लिए।विनीतखण्ड गोमतीनगर में पूर्व विधायक हीरालाल गौतम रहते हैं। उनका एसबीआई विधानसभा शाखा में बचत खाता है। जालसाजों ने हीरालाल के एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर बेंगलुरु से 47 हजार रुपये पार कर दिये। मोबाइल पर रुपये निकलने का मैसेज आने पर उन्हें ठगी की जानकारी हुई। पूर्व विधायक हीरालाल गौतम ने हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज करायी है।वहीं, विकासनगर निवासी अर्चना खरे के पास कुछ दिन पहले कॉल आयी। फोन करने वाले ने जानकारी हासिल की और फिर खाते से 49 हजार रुपये उड़ा लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने विकासनगर में रिपोर्ट दर्ज करायी। उधर, देवीखेड़ा पीजीआई में रिटार्यड सैन्य अधिकारी विजय सिंह परिवार के साथ रहते हैं। उनका बचत खाता बैंक ऑफ इण्डिया में है। रिटायरमेंट के बाद श्री सिंह काफी वक्त का एक अस्पताल में बतौर एकाउंटेंट काम कर रहे हैं। श्री सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले वे अस्पताल से घर आ रहे थे। रास्ते में उनका पर्स कहीं गिरकर खो गया।

दागी सांसदों, विधायकों की सही संख्या बताएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा हाई कोर्ट से कहा है कि वे सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सारे मामलों का पूरा विवरण पेश करें। अदालत ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वे इस समय लंबित उन मुकदमों की सही संख्या बताएं, जिन्हें पूरी तरह सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालतों को सौंपा जाना है। जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने इस तय का संज्ञान लिया कि 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें गठित की जा चुकी हैं। अदालत ने राज्यों और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि अपेक्षित जानकारी उसके समक्ष 10 अक्टूबर तक पेश की जाए। इस मामले में अब 10 अक्टूबर को आगे सुनवाई होगी। अदालत ने अपने आदेश में इस तय को नोट किया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब और चंडीगढ़ सहित 25 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट के एक नवम्बर, 2017 और इस साल 21 अगस्त के आदेश के बावजूद अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के बीच फिर आया लाउडस्पीकर, गुड़गांव में सील हुई मस्जिद

लखनऊ। गुडगाँव के शीतला माता कॉलोनी में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों पर मचे विवाद के एक हफ्ते बाद, आज बुधवार को गुडगाँव नगरनिगम ने मस्जिद को सील कर दिया है. इस मामले में एमसीजी कमिश्नर ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना (आईएएफ) गोला बारूद डिपो के बहुत करीब है. कुछ दिन पहले क्षेत्र में कुछ हिन्दू लोगों ने लाउडस्पीकरों की आवाज से परेशानी होने के कारण आपत्ति उठाई थी, जिसके कुछ दिन बाद नगर निगम द्वारा ये कदम उठाया गया है.एमसीजी आयुक्त यशपाल यादव ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक मस्जिद को बंद किया गया है, क्योंकि कानून के अनुसार आईएएफ डिपो के 300 मीटर के दायरे के अंदर

किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है, और मस्जिद उसी दायरे में आती है, इसीलिए उसे सील किया गया है.

इससे पहले 6 सितम्बर को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की गई थी, जिसमे मुस्लिम एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को एक पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि ष्दो-तीन दिन पहले कुछ असामाजिक तत्व हमारे इलाके में आए थे, उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस कमिश्नर को पत्र भी दिया था, जिसके बाद 5 सितम्बर को सेक्टर 5 के एस.एच. ओ ने दोनों दलों को बुलाकर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा था.ष मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष हाजी शहजाद खान ने आरोप लगाया कि लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के बाद भी गांव के बाहर के कुछ हिन्दू संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें गांव में एक मस्जिद खलने लगी और उन्होंने हमे जान से मारने और हमारे घरों को जला देने की धमकी दी है. हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे गुरुवार (6 सितंबर) को डीसी से नहीं मिल सके क्योंकि वह अन्य बैठकों में व्यस्त थेष उन्होंने कहा कि ष्तीन मंजिला घरों में प्रार्थनाओं के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर संगठन ने बुधवार को विरोध किया था. अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के राजीव मित्तल ने कहा था कि एसएचओ को एक पत्र भी दिया गया था, जिसमें माइक और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और घर पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार के प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्राचार्यों की अर्हताओं में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जबकि बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए निरूशुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखायी गई।

श्री सिंह ने बताया कि वर्षा जल संचयन भू-जल के संबंध में फैसला आया है, जिसमें तालाब की मरम्मत और पेड़ लगाने जैसी योजनाएं बनाई गई है। नए और पुराने

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन

राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट अगर काम करना चाहे तो उनके कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालयों के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। उन्होंने बताया कि बागपत के बड़ौत तहसील के ग्राम औरंगाबाद जटौली में केंद्रीय

विद्यालय की स्थापना के लिए कुल 2.0240 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 3321.14 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गयी। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मंजूरी मिल गयी है। कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं। श्री सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए अनुदान और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में उ.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर उ.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी दी गई। श्री सिंह ने बताया कि भूगर्भ जल के स्तर में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना शुरु करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना में लघु सिंचाई विभाग एक से पांच हेक्टेयर के परंपरागत रुप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास और प्रबंधन करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सात नए एवं पांच निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मैडिकल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कंसल्टेंट के रुप में संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गयी।

योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों की नीति हो रही है फेल

प्रतापपुर। योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के वादे शायद वादे ही रहेंगे बतातें चलें की प्रतापपुर से बादशाहपुर मार्ग को जोड़ने वाली सडक प्रतापपुर तिराहे पर लगभग दो महीने से धंसी है जिससे आने जाने वाले राहगीर गिर कर हो जाते हैं

चोटिल और बाजारवासियों को आये दिन करना पड़ता है दिक्कतों का सामना धंसी सड़को के वजह से हर दिन लगता है जाम।धंसी सड़कें ही बन रही हैं एक्सीडेंट की कारण जिससे साल भर मे हजारों को गवाना पड़ता है जान।

मोहर्रम त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक

सिकंदरपुर (बलिया)। मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनजर पीस कमेटी की एक बैठक स्थानीय पुलिस चौकी के प्रांगण में हुई। इसमें त्योहार के अवसर पर नगर में साफ-सफाई, बिजली व पानी की उपलब्धता, जुलूस के गुजरने के मार्गों से अतिक्रमण हटाने, अवरोध पैदा करने वाले बिजली के तारों को हटाने आदि मुद्दों के बारे में चर्चा किया गया। साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया।

थानाध्यक्ष अनिल चंद तिवारी ने कहा कि त्यौहार सद्भाव व प्रेम के प्रतीक होते हैं। इन्हें सद्भाव पूर्वक वातावरण में मनाया जाना चाहिए। बिजली के लटके व ढीले तारों को ठीक करने, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था का विद्युत विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देश दिया। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने त्यौहार को आपसी सहयोग से शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लोगों से अपील किया। छोटी मोटी घटनाओं की सुचना को भी तत्काल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को देने की सलाह दिया। समर बहादुर सिंह चेयरमैन रवींद्र वर्मा, प्रयाग चौहान, डॉक्टर उमेशचंद, लालवचन शर्मा, बोख्तियार अहमद, लाल बच्चन प्रजापति, बिहारी पांडेय, मुमताज खान, बल्लू मास्टर, इम्तियाज अंसारी, बैजनाथ पांडेय, प्रमोद गुप्ता, उमाशंकर राजभर, ओंकार चंद सोनी आदि मौजूद रहे।

शिवपाल के समाजवादी सेकुलर मोर्चे के 9 प्रवक्ता नियुक्त

लखनऊ। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नई पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चे का कामकाज विधिवत शुरू कर दिया है। उन्होंने समाजवादी सेकुलर मोर्चे के लिए 9 प्रवक्ताओं के नामो की घोषणा की है।

जिन 9 लोगों को पार्टी का प्रवक्ता न्युक्त किया गया है उनमे सैयद शादाब फातिमा, दीपक मिश्र, नवाब अली अकबर, सुधीर सिंह, प्रोफेसर दिलीप यादव, अभिषेक सिंह आशू, मोहम्मद फरहत रईस खान और अरविंद यादव के नाम शामिल हैं।

कहा जा रहा है कि जिन लोगों को समाजवादी सेकुलर मोर्चे का प्रवक्ता बनाया गया है उन्हें कभी समाजवादी पार्टी में हाशिये पर धकेल दिया गया था और उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था।

इससे पहले लखनऊ में श्रीकृष्ण वाहिनी के कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने महाभारत का जिक्र करते हुए इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव की तुलना कौरवों से कर दी। शिवपाल ने कहा कि पांडवों ने कौरवों से पांच गांव मांगा था। मैंने तो सिर्फ सम्मान ही मांगा

था।

शिवपाल ने कहा कि वे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे. लंबे इंतजार के बाद यह कदम उठाया। अब कदम पीछे नही खीचेंगे. शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने नेता जी (मुलायम सिंह यादव) से पूछ कर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है। यह एक धर्मयुद्ध है, जिसमें जीत धर्म और सत्य की होती है। ये लड़ाई समाजिक परिवर्तन और न्याय की है।

शिवपाल यादव ने कहा कि साथ वही हैं जिनको मैंने ज्यादा नहीं दिया. मैं आपस में नहीं लड़ना चाहता था। हमारे लोग मेरे विरोधी की मदद कर रहे थे, बहुत से लोग बेईमानी से ले गए।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत काम करना चाहते थे। जो द्वार पर आए उसे कुछ मिलना चाहिए। मैंने श्री कृष्ण की तरह दे दिया, लेकिन वे सुदामा नहीं निकले।

शिवपाल ने कहा कि जो महान हुए हैं उन पर संकट पड़ा है। धर्म पर चलने वाले की कभी हार नही होती। अब तो कंस का नाम लेने से पता हो जाता है। आज भी कंस पैदा होते हैं. बहुत कंसहैं. रावण मारा गया और कंस भी मारा गया।

सीएम ने पांच हवाई सेवाओं का किया शुभारम्भ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग पर स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा पांच नये वायुमागरे पर हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के शुभारंभ के बाद गोरखपुर-बेंगलुरू, वाराणसी-कोलकाता, वाराणसी- बेंगलुरू, कानपुर-मुम्बई व कानपुर-कोलकाता के इन वायुमार्गों पर टिकट बुकिंग प्रारम्भ कर दी गई। अक्टूबर और नवम्बर 2018 में इनका संचालन प्रारम्भ हो जाएगा।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वायुसेवा के विस्तार की असीम सम्भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आमजन को अच्छी व सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए देश में यूडीएएन (उड़े देश का आम नागरिक) योजना को संचालित किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा

करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए आवागमन की बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पाइसजेट एयरलाइंस को उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वायुमार्ग पर प्रारंभ की गई वायु सेवाओं के लिए स्टेट इंसेंटिव एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। स्पाइसजेट एयरलाइंस के चीफ मार्केटिंग आफीसर देबाजो महर्षि और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सीएस पलनी ने सम्मान स्वरूप मुख्यमंत्री को कानपुर-मुंबई तथा वाराणसी-कोलकाता की लाइट के बोर्डिंग पास प्रदान किए। महर्षि द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले तक स्पाइस जेट द्वारा उत्तर प्रदेश से सिर्फ तीन हवाई सेवाएं संचालित की जा रही थीं।

डीएम की पहल पर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आई आगरा की गैर सरकारी संस्थाएँ, भेजी राहत सामग्री

गोण्डा। जिलाधिकारी कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव की पहल पर जनपद आगरा की कई गैर सरकारी संस्थाओं ने गोण्डा बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।जिलाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगरा से गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भारी मात्रा में मदद सामग्री भेजी गई है। बताते चलें कि जिलाधिकारी जनपद आगरा में पूर्व में तैनात रहे हैं। आगरा विकास मंच, कपड़ा बैंक आगरा सहित कई अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने जिलाधिकारी के व्यक्तिगत अनुरोध पर गोण्डा के

बाढ़ पीड़ितों के लिए धोती, साड़ी, सलवार, शूट,गमछा,कुर्ता और बच्चों के कपड़े ट्रक पर लदवाकर भेजा है।

जिलाधिकारी के आदेश पर एआरटीओ सर्वेश गौतम ने बाढ़ राहत सामग्री मंगवाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित दोनों तहसीलों करनैलगंज व तरबगंज के अत्यन्त गरीब बाढ़ प्रभावितों को तहसील प्रशासन के माध्यम से चिन्हित करा लिया गया है जिन्हें कपड़े व अन्य प्राप्त रहात सामग्रियों का वितरण कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी व दोनों तहसीलों के एसडीएम को वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीएसआर कोष के जरिये राज्य के विकास में योगदान करें उद्योग : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक घरानो से अपील की कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष के जरिये वे राज्य के चर्तुमुखी विकास में योगदान दें। उन्होने दावा किया कि शौचालयों के निर्माण में रिकार्ड बनाने के अलावा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में उपलब्धि हासिल करने में सीएसआर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा खुले में शौच मुक्त और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सीएसआर कोष ने अहम भूमिका निभायी है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा,पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी सीएसआर सहायक रहा है। देश का एक बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में जनसुविधाओं की जरूरत भी बडी है। इसलिये उद्योगों को सीएसआर कोष के जरिये राज्य की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिये। ९ उन्होने कहा कि पिछले 16 महीनों के दौरान राज्य में एक करोड़ 35 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जिनमे से 90 लाख शौचालय इसी साल बनाये गये। राज्य के शहरी और

ग्रामीण इलाकों में 15 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माणाधीन है।

विभिन्न उद्योग संघों द्वारा लोकभवन में आयोजित सीएसआर कान्क्लेव का उदघाटन करते हुये श्री योगी ने साफ किया कि राज्य को खुले में शौच मुक्त निर्धारित समयावधि में करने के लिये सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने 59 हजार गांवों में शौचालयों के निर्माण के लिये ढाई लाख राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया है। शौचालयों के निर्माण कार्यों की देखरेख के लिये स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गयी है।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा दिया है। यह तोहफा है उनका मानदेय बढ़ाने का। नरेंद्र मोदी एप के जरिये आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने इन कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की। इसी के साथ उन्होंने इन कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले महीने से 4500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें 3000 रुपये मिलते थे। वहीं जिन कार्यकर्ताओं को 2200 रुपये मानदेय मिलता था उन्हें अब 3500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर, 2018 से लागू होगा। यह राशि केंद्र के हिस्से की है।

मानदेय बढ़ाने के अलावा आशा वर्कर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त दी जाएगी। दो–दो लाख की इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होगा व पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कई जिलों में सरकार द्वारा स्मार्टफोन भी मुहैया कराए गए हैं। ये वर्कर्स अब तक अपना जो काम रजिस्टर में करती थीं, वो सब अब स्मार्टफोन पर करेंगी।

मोदी के तोहफे की बारिश बस यहीं खत्म नहीं हुई। जहां पहले 42 दिनों में 6 बार आशा वर्कर्स बच्चे के जन्म के बाद उसके पास जाती थीं, वहीं अब वे 11 महीने में 15 बार बच्चे के पास जा सकेंगी। आशा कार्यकर्ताओं के काम की सराहना कर मोदी ने उनका धन्यवाद किया।

भाजपा ईवीएम के भरोसे दम भर रही है : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है।अखिलेश ने बीजेपी के 50 सालों तक सत्ता में रहने पर तंज कसते हुए लिखा कि बीजेपी का विजन सिर्फ टेलीविजन और बीजेपी दावा करती है की वो 50 सालों तक सत्ता में रहेगी ऐसा लगता है की उन्हें म्टड पर पूरा भरोसा है।

सपा प्रमुख ने नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक मोदी सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए लिखा कि नोटबंदी, जीएसटी, दलित, किसान, नारी व युवा उत्पीड़न, महँगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल–डीजल के रोज बढ़ते दाम, अमीरों से मुनाफाख़ोरी के सौदे भाजपा के जन विरोधी कारनामे रहे हैं।

अब तो जनता को ऐसा लगने लगा है कि भाजपा जनता को दुख देने और परेशान करने की एक प्रयोगशाला खोल के बैठी है।

नोटबंदी, जीएसटी, दलित, किसान, नारी व युवा उत्पीड़न, महँगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल–डीजल के रोज बढ़ते दाम, अमीरों से मुनाफाख़ोरी के सौदे भाजपा के जन विरोधी कारनामे रहे हैं. अब तो जनता को ऐसा लगने लगा है कि भाजपा जनता को दुख देने और परेशान करने की एक प्रयोगशाला खोल के बैठी है. अखिलेश ने कहा कि जनता 50 हफ्तों के अंदर ही मोदी सरकार को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अहंकारी कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक भाजपा सरकार ही रहेगी।

मीडिया, सांविधानिक संस्थानों व लोगों की भीड़तंत्रीय हत्याओं के बाद अब क्या ये जनता के सरकार चुनने के अधिकार की भी हत्या करेंगे, जो ऐसे तानाशाही बयान दे रहे हैं। देखियेगा जनता अगले 50 हफ्तों से पहले ही इनको जवाब दे देगी।

संक्षिप्त समाचार

27 रूटों पर दौड़ेंगी स्लीपर बसें

लखनऊ। स्लीपर बस योजना वर्ष–2018 में अनुबंधित बस मालिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। स्थिति यह है कि 12 सितम्बर को टेंडर डालने के अंतिम दिन आधा दर्जन निजी बस आपरेटरों ने ही हिस्सा लिया। इन सभी ने 42 बसों के अनुबंध के लिए लिए टेंडर डाले। इनमें कई ऐसे भी टेंडर डाले गए, जिनपर दो निजी आपरेटरों ने मिलकर टेंडर डाला है। ऐसे में बसों की संख्या और कम होती नजर आ रही है, जबकि परिवहन निगम की ओर से 57 स्लीपर बसों की मांग को देखते हुए टेंडर जारी किए गए थे। परिवहन निगम मुख्यालय में तैनात प्रधान प्रबधंक पी. आर. बेलवारिया ने बताया कि बुधवार की दोपहर तक 42 बसों के अनुबंध करने को लेकर टेंडर आए है, जबकि 57 बसों के अनुबंध के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इस संबंध में शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रबंध निदेशक को सौपेंगे। उनकी अनुमति के बाद टेंडर की तिथि बढ़ाए जाने पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के 27 रूटों पर स्लीपर बसें संचालित करने का प्रस्ताव है। इन रूटों पर 57 स्लीपर बसों का बेड़ा होगा। टेंडर में बसों की संख्या कम है। ऐसे में प्रबंध निदेशक की ओर से जो भी निर्देश दिए जाएंगे। उसी आधार पर बसों की संख्या बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश अनुबंधित बस मालिकों को देंगे।

नौचंदी एक्स. रद्द होने पर भड़के यात्री

लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुबह सहारनपुर से इलाहाबाद जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस निरस्त कर दी गयी। इसको लेकर मुसाफिर भड़क गये। इस ट्रेन से इलाहाबाद व अन्य स्टेशनों पर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी। कुछ यात्रियों का यह भी कहना था कि नौचंदी एक्सप्रेस अचानक निरस्त कर दिया गया।

11 घंटे लेट आयी साबरमती एक्सप्रेस

लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, आगरा–कोलकाता एक्सप्रेस, देहरादून से हावड़ा जाने वाली दून एक्सप्रेस, झांसी पैसेंजर, राजगीर (पटना) से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस चार से 11 घंटे की देरी से यहां आयीं जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।

आरटीओ कार्यालय की ऑनलाइन व्यवस्था पर पुरस्कृत हुए अधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन व्यवस्था पर विभाग को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया गया है। यूपी में सौ फीसदी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन से लेकर ऑनलाइन परमिट व ई–चालान की पहल करने दिया गया है।सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय दामले ने विभाग के अपर परिवहन आयुक्त वी.के. सिंह व आरटीओ (आईटी सेल) संजय नाथ झा को नई दिल्ली के इंडिया हेबिटैट सेंटर में आयोजित वाहन व सारथी वर्कशाप में पुरस्कार प्रदान किया। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में सारथी फोर साफ्टवेयर के जरिए डीएल संबंधी कायरे के सौ फीसदी आवेदन ऑनलाइन करने में सफलता हासिल हुई है। साथ ही वाहन फोर साफ्टवेयर में ऑनलाइन परमिट आवेदन और ई–चालान सेवा शुरू करने की पहल की जा रही है।

ऑन लाइन मिलेगा रिफंड व ध्वस्तीकरण का आदेश

लखनऊ। प्राधिकरणों व आवास विकास की योजनाओं में किसी आवंटन आदेश की डुप्लीकेट कॉपी व किसी भवन के ध्वस्त करने अथवा सील करने का तथा रिफंड धनराशि दिए जाने की सुविधा ऑनलाइन होगी। इन सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। इससे आवेदकों को निश्चित समय में लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने इस सम्बंध में आवास आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को आदेश जारी कर दिया है।

पतियों की लंबी उम्र के लिये महिलाओं ने रखा हरतालिका तीज व्रत

लखनऊ। राजधानी में हरतालिका तीज के अवसर पर पत्नियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिये बुधवार को निर्जला व्रत रखा। ये व्रती पत्नियां अगले सुबह गुरुवार के दिन सूर्योदय के बाद अपना उपवास तोड़ेंगी। यूं तो पति के दीर्घायु होने और उनकी रक्षा के लिए धर्मशास्त्रों में कई व्रत–त्योहारों का जिक्र है, लेकिन इनमें श्हरितालिका तीजश व्रत का बेहद महत्व है। तीज पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गोमतीनगर निवासी व्रती माया ने बताया भारतीय परंपरा व त्यौहारों का एक अपना अलग ही महत्व है। यहां होने वाले व्रत–त्यौहारों में मनुष्य सहित जीव–जगत के कल्याण की कामना की जाती है। ऐसे ही हरतालिका तीज का

त्यौहार है।

बर्लिंगटन स्थित ओसीआर निवासी सोना तिवारी ने बताया कि आज का दिन पतियों की मंगलकामना का होता है। उन्होंने कहा इस तीज पर्व पर मैं अपने सुख–दुख के साथी के आगे बढ़ते रहने की कामना करती हूं। वहीं गोमतीनगर स्थित विनीत खंड की माया पांडेय ने बताया कि इस दिन गौरी–शंकर की पूजा की जाती है। महिलाएं पूरा दिन भजन–कीर्तन करती हैं। उन्होंने बताया कि वहीं इस पावन पर्व पर कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती हैं। निशातगंज निवासी पल्लवी गोस्वामी ने कहा मां सती ने पार्वती के रुप में पुनर्जन्म लेकर घोर तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। शादीशुदा महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके पति की लंबी उम्र और सौभाग्य का वरदान मांगती हैं।

ब्लॉक कार्यालय में बना शौचालय गंदगी का अंबार

रायबरेली। एक तरफ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार मिल कर स्वच्छता मिशन पर जोर देकर ग्रामीण आँचलो तक योजना चलाकर स्वच्छता मिशन का बढावा दे रही। वही खीरों ब्लाक परिसर सभागार कक्ष के बगल मे बना शौचालय गन्दगी का अम्बार दिख रहा, जिस कार्यालय मे60 ग्राम पंचायत के लोगो का आवागमान रहता वहा पर लघुशंका को जाने के लिये लोगो को सोचना पड़ रहा।

जिस कार्यालय मे क्षेत्र पंचायत से वाल बाउण्ड्री आवास से लेकर मरम्मत कार्य ढेकेदारी मे चल रहा पर उक्त शौचालय की तरफ डी.डी.ओ.से लेकर सी. डी.ओ.तक ब्लाक कार्यालय मे आकर क्षेत्र मे ओ.डी.एफ. योजना से बनाये गये शौचालयो की जाँच करके वापस चले जाते पर आज तक खण्ड विकास अधिकारी भी उक्त शौचालय की मरम्मत तो दूर कभी उस शौचालय की तरफ सफाई के लिये निगाहे केन्द्रित नही होती है।

जानकारी के अनुसार वाल बाउण्ड्री की मरम्मत के दौरान डी.डी.ओ.साहब कार्य की जाँच कर रहे थे औचक निगाहे एक भवन की तरफ पड़ी जिस मे लिखा कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पं०) देख भड़क गये साथ मे खण्ड विकास अधिकारी को आदेशित कर तत्काल पोतवाया जाय लेकिन साहब का आदेश रद्दी टोकरी मे डाल कर मजाक उड़ाया गया जिस ब्लाक कार्यालय मे लघुसंका के लिये लोगो को सोचना पड़े वहा शौचालय गन्दगी के आँशू बहा रहा है।

कांग्रेसियों ने मंहगाई के विरुद्ध प्रदर्शन कर प्रशासन को परेशान किया

उन्नाव। पूर्व सांसद अन्नू टण्डन के नेतृत्व में सोमवार को डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के बढ़े हुये दामों से नाराज कांग्रेसियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रशासन के पसीने उड़ा दिया। कलक्टरगंज फाटक से शुरु हुये प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलायें व पार्टी पदाधिकारियों के साथ–साथ जिले भर से आये हुये कार्यकर्ता बैलगाड़ी, तांगा से सरकार विरोधी नारे लगाते हुये निकल पड़े।

पूर्व सांसद स्वयं बैलगाड़ी में बैठकर हाथ में गैस सिलेन्डर लेकर डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़े हुये दाम का विरोध कर रही थी। वही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी–अपनी मोटर साईकिल से जुलूस निकाल कर पैदल ही धकेल कर अपना विरोध दर्ज कराया। अन्नू टण्डन ने कहा कि आज कांग्रेस का यह आन्दोलन देश में बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में भारी बढ़ोत्तरी से आज आम जन बेहाल हो गया और कांग्रेस के प्रदर्शन में आम जनता भी भागीदारी कर रही है। शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला ने आन्दोलन का संचालन कर रहे थे।

शिवपाल ने भतीजे अखिलेश की तुलना कौरवों से की

लखनऊ। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाकर अपने ही भतीजे अखिलेश के खिलाफ ताल ठोक रहे चाचा शिवपाल ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश पर हमला बोला। खुद की तुलना पांडव से और अखिलेश गुट की तुलना कौरवों से करते हुए चाचा शिवपाल ने कहा, श्मैंने सोचा था कि अलग–अलग लड़ेंगे तो नुकसान सभी का होगा लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग हमें ही हराने में लगे रहे, लेकिन फिर भी हम जीते। कुछ कम वोट जरूर मिले। पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, हमने तो सम्मान के अलावा कुछ नहीं मांगा था। हमने कहा था

कि हमें मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है।इ

शिवपाल यादव यहीं नहीं रुके और अखिलेश को अहंकारी बताते हुए कहा, सत्ता पाकर लोगों में अभिमान आ जाता है, रावण, कंस और दुर्योधन को भी अभिमान आया था, तो फिर अहंकारी का नाश ही होता है। मैंने कभी कोई पद नहीं मांगा। कभी राजनीति में आने की नहीं सोची क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन राजनीति में आना पड़ा। लेकिन तब लोग बेईमान नहीं थे,। हम लोग महीनों साइकिल चलाते थे आज कोई 2 घण्टे भी साइकिल चलाते हैं तो बड़ा प्रचार करते हैं। बहुत से लोग बिना मेहनत के सब कुछ चाहते हैं। अपनी नई पार्टी को लेकर शिवपाल यादव ने कहा, समाजवादी सेक्युलर मोर्चा सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के साथ ही धर्म की भी लड़ाई लड़ेगा। मोर्चे के संघठन का बहुत जल्दी निर्माण करेंगे। अभी तो हमें 75 जिलाध्यक्ष, 75 जिलों के प्रभारी बनाएंगे, सोचो जब संगठन बनाएंगे तो क्या हाल होगा। हमारी पार्टी समाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी।

खुद शिवपाल मंच से कई बार कह चुके थे कि अब पार्टी के अंदर मेरे कोई अहमियत नहीं रह गई है। पार्टी को नए तरीकों से चलाया जा रहा है।

कूड़ा निस्तारण सबकी जिम्मेदारी : मनोज सिंह

लखनऊ। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कूड़े की समस्या के समाधान के लिए हर आदमी को इसके प्रबंधन की दिशा में योगदान देना होगा। शहरी स्वच्छता को दिए जा रहे महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं का फोकस निर्माण पर बना रहा है जबकि संचालन और रखरखाव की उपेक्षा की गयी। इसी का नतीजा है कि योजनाएं बनीं तो पर बाद में बन्द हो गयीं। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थानीयकृत समाधान विकसित करने पर भी बल दिया। ''शहरी स्वच्छता के लिए अभिनव समाधान को बढ़ाने के लिए साझेदारी' पर गोमती नगर स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में नागरिक समाज संगठनों, सरकारी अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और साधारण नागरिकों के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने राज्य के शहरों में सतत स्वच्छता समाधान प्राप्त करने के लिए भागीदारी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गयी। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और सरकार के नए शहरी एजेंडा को प्राप्त करने पर भी विचार हुआ। नगर विकास विभाग के सचिव जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि स्वच्छता के सतत समाधान लागू किए जाने पर सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है। आम लोगों की भागीदारी से योजनाएं अधिक प्रभावी होंगी। झांसी में निपटान सुधार समितियों के नागरिक नेताओं ने झांसी नगर निगम (जेएमसी) के साथ जुड़ने के अपने अनुभव साझा किए। भारत के यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के शूविक दत्ता ने कहा कि नागरिक समाज संगठनों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग गरीबों और हाशिए के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। स्वच्छता के मुद्दे पर नागरिकों, पहुंच और सशक्तिकरण की भागीदारी महत्वपूर्ण है। पीआरआईए द्वारा आयोजित झांसी में महिला स्वच्छता श्रमिकों पर एक शोध के निष्कर्ष भी साझा किए गए थे। अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं अधिकांश स्वच्छता श्रमिकों का काम करती हैं।

विरोध के बीच काटी 42 बकायेदारों की बिजली

लखनऊ। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए बुधवार को मध्यांचल के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर बाराबंकी व सीतापुर की विजिलेंस टीमों ने लेसा सिस गोमती के अमीनाबाद डिवीजन के रस्सी बटान व रायबरेली की विजिलेंस टीम के साथ हुसैनगंज के मछली मोहाल में लेसा की टीमों ने संघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अचानक बाहर की पुलिस को देखकर लोग भड़क उठे और हंगामा करना शुरू कर दिया। बाद में मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। इस दौरान रस्सी बटान में 17 व मछली मोहाल में 13 लोगों को बिजली चोरी करते पाया गया जिसमे इनके खिलाफ सम्बधित थानों में बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और मछली मोहाल में 27 तथा रस्सी बटान में 15 बकायेदारों की बिजली काट दी गयी। एमडी मध्यांचल संजय गोयल के निर्देश पर बुधवार को बाराबंकी, सीतापुर व रायबरेली की विजिलेंस टीमों को बुलाकर अमीनाबाद व हुसैनगंज डिवीजन में छापेमारी के लिए लगाया गया।

इस दौरान बाराबंकी व सीतापुर की विजिलेंस टीमों के साथ लेसा की टीमों ने अमीनाबाद के रस्सी बटान में संघन चेकिंग करने पहुंचे। अचानक बाहर के पुलिस को देखकर लोग भड़क उठे और हंगामा शुरू कर दिया। बाद में अमीनाबाद के अधिशासी अभियंता के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हो सके। इसके बाद टीमों ने यहां पर 152 उपभोक्ताओं के परिसर की जांच की। इस दौरान 15 बकायेदारों का बिल न जमा होने पर बिजली काट दी गयी और 17 लोगों को बिजली चोरी करते पाये जाने पर इनके खिलाफ अमीनाबाद थाने में बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। इस दौरान टीमों ने सात लोगों के खराब मीटर बदल दिये। इसी तरह रायबरेली की विजिलेंस की टीम ने हुसैनगंज डिवीजन के मछली मोहाल में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यहां पर भी उपभोक्ताओं के विरोध के बीच 148 उपभोक्ताओं की जांच की गयी।

बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा

उन्नाव। ग्रामीणो ने उन्नाव–हरदोई मार्ग स्थित दोस्ती नगर नहर के निकट जाम लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग उठायी। इसके चलते वाहनो का लम्बा काफिला लग गया। घंटो पुलिस को जाम खुलवाने के लिये मेहनत करनी पडी। ऐरा भदियार पावर हाउस से जुडे लगभग 200 गांवो में लगभग 1 सप्ताह से विद्युत आपूर्ति बन्द है। बताते चले कि पावर हाउस में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्रामीण कई बार कुन्दनरोड तथा सफीपुर पावर हाउस व कब्बाखेडा पावर हाउस से लाइन जुडवाने की मांग कर चुके है। विभागीय अधिकारी उन्हे कोरा अश्वासन देकर चलता करते रहें। सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे ग्रामीणो का आक्रोश उबाल मार गया। भारी संख्या में एकत्र होकर उन्नाव–हरदोई मार्ग को जाम कर दिया। घंटो जाम लोग फंसे रहे। जैसे ही मामले की जानकारी आलाधिकारियों को हुई वह घटना स्थल पर पहुच कर आक्रोशित ग्रामीणो को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। थाना, दोस्ती नगर, रामसिंहखेडा, रऊ करना, बौनामऊ, रग्घाखेडा, हिन्दूखेड़ा

दशहरा बाजार से हटाए गए अतिक्रमण से परेशानी हो सकती है

बिसवां–के दशहरा बाजार के निकट स्थित मछली मंडी व मीट दुकानदारों को पालिका प्रशासन ने एलाउंसमेन्ट करवा कर जमीन खालीकरने का आदेश दे दिया दुकानों को रेलवे क्रासिंग सीतापुर रोड पर शिफ्ट करवा कर। खाली पड़ी जमीन के चारों तरफ रक्खी दुकानों को बगैर नोटिस दिये। उपजिलाधिकारी मय पुलिस बल व नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा (जे,सी,बी,) की सहायता से तोड़ फोड़ कर लाखों रुपए के माल की बर्बादी की गई।

जब की उनको कहि पर बसाने के लिए जगह का इंतजाम भी नही किया।अब सवाल यह उठता है कि अतिक्रमण सिर्फ वहीं पर था।नगर के बड़े चौराहे व जहाँगीराबाद रोड पर तो जाम की बड़ी दिक्कतें रहती है।जिस से आये दिन हादसे होते रहते है।और कई जानें भी जा चुकी है। पहले तो उन जगहों पर अतिक्रमण हटाना चाहिए था पर सुरुआत मछली मंडी से हुई।लेकिन दूसरे व तीसरे दिन भी अतिक्रमण और जगहों से नही हटाया गया।इस बात को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

इसी क्रम के साथ खाली कराई गई जमीन के बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त गाटा संख्याये कैथी टोला निवासी प्रेम नरायड ,बद्री प्रसाद,ललित मोहन,आदि लोगों के नाम तहसील के अभिलेखों में फर्जी दर्ज किया गया है। इसी भूमि को नगर पालिका राजा महमूदाबाद से लीज(करार) पर ली गयी भूमि बताता है।यह जांच का विषय है। जब कि गाटा संख्या 1470 व 71 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राजा महमूदाबाद के द्वारा किये गए बैनामों के आधार पर कई मुकदमें न्यालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय सीतापुर के यहां विचाराधीन है। सूत्रों की माने तो उनका यह भी कहना है कि इन्हीं प्लॉटों को चेयरमैन के पति राजू जैन, नीरज जैन, व उनके भूमाफिया सहयोगी खरीदना चाहते हैं। इसी कारण अतिक्रमड हटाने का सहारा लेकर प्रशासन की मदद ली जा रही है।आपको बता दें कि इससे पूर्व भी पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा जमीन खाली कराने का प्रयास किया जा चुका है।

ई–रिक्शा चालक से मांगी रंगदारी, दी धमकी

लखनऊ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में ई–रिक्शा चलाने के एवज में दबंग ने रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित चालक ने परेशान होकर पुलिस से आपबीती बतायी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

जानकीपुरम विस्तार में विजय कुमार परिवार के साथ रहता है। विजय ई–रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। विजय का कहना है कि बीते सोमवार रात वह सवारी लेकर इंजीनियरिंग कालेज चौराहा गया था। उसे दबंग देवेन्द्र सिंह ने रोक लिया।

भारत पर सिर्फ विदेशी बना रहे अच्छी फिल्में-अनुपम खेर

अनुपम खेर का मानना है कि भारत पर अच्छी फिल्में सिर्फ विदेशी फिल्मकार ही बना रहे हैं. ऐसा भारतीय फिल्मकार नहीं कर रहे हैं. अनुपम खेर इस बात से हैरान हैं कि भारत पर महान फिल्में हमारे डायरेक्टर क्यों नहीं बना रहे.

सितंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमलों पर आधारित ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक एंथनी मारस की पहली फीचर फिल्म 'होटल मुंबई' के टोरंटो में प्रीमियर पर खेर ने कहा, "यह काफी रोचक है कि फिल्म 'गांधी' भी किसी विदेशी ने बनाई थी और अब 'होटल मुंबई' भी एक विदेशी ने बनाई है."

अनुपम ने आगे कहा, "धन्यवाद, एंथनी यह फिल्म बनाने के लिए. यह फिल्म उन सभी को समर्पित एक श्रद्धांजलि हैं, जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया. "

इस संवाददाता सम्मेलन में अनुपम ने खुलासा किया कि 'होटल मुंबई' उनके करियर की 501वीं फिल्म है. यह फिल्म 7 सितंबर को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई.

सोपोर मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर

श्रीनगररू उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पुलिस के विशेष अभियान दस्ते ने सुबह सोपोर के तानकीपोरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान छेड़ा। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी गोलियां चलाईं।

आसपास के इलाके में किसी प्रकार के प्रदर्शन को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। वहीं साथानीय लोगों ने सुरक्षाबलों के अभियान में बाधा डालने के लिए पत्थरबाजी की जिसके चलते प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात के तौर पर सोपोर में भारत संचार निगम लिमिटेड समेत सभी सेल्यूलर कंपनियों की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दीं। उत्तरी कश्मीर में ट्रेन सेवाएं पहले ही स्थगित कर दी गई हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया जातिगत राजनीति करने का आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सपा पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा से बड़ी जातिगत राजनीति करने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं है. उन्होंने पेपर लीक होने के मामले पर कहा की नौजवान तो योग्य है पर सरकार ही अयोग्य है. मंगलवार 11 सितम्बर को नव साईकिल यात्रा का स्वागत करते हुए सपा अध्यक्ष ने पेट्रोल–डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा की तेल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र में बैठी सरकार जिम्मेदार है.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के फैसलों पर जनता कुछ नहीं कहती लेकिन वह समय जल्द ही आने वाला है जब जनता बीजेपी को जवाब देगी. पूरा देश जानता है कौन

धोखा दे रहा है .भाजपा के जातीय सम्मलेन पर यादव ने कहा कि बीजेपी ही तो सब कुछ है. उनके मंत्री स्वयं ही बोलते हैं कोर्ट भी हमारा, सरकार भी हमारी, कार्यपालिका भी हमारी, विधायिका भी हमारी. बीजेपी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है, सबसे ज्यादा जातिवाद कोई पार्टी फैलाती है तो वह बीजेपी ही है. राज्य की स्वास्थय व्यवस्था पर सवालिया उंगली उठाते हुए अखिलेश ने कहा नर्सें ऐसा इंजेक्शन लगाती हैं की महिलाओं की मौत हो जाती है. बीमारियों को लेकर सरकार को कोई चिंता नहीं है,पता नहीं इंजेक्शन में दवा थी या पानी ? सरकार लापरवाह है है और जनता इसका जवाब भी देगी.

अखिलेश यादव की पार्टी मध्यप्रदेश के विधानसभ चुनाव में समस्त सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज कल उनका मुख्य काम 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करना है. बता दें की नव साईकिल यात्रा वाराणसी से लखनऊ आज पहुंची है।

किसके कहने पर सीबीआई ने बदला लुकआउट सर्कुलर? माल्या को मिला विदेश भागने का मौका

नई दिल्ली। विजय माल्या को लेकर देश में सियासी घमासान जारी है. सरकार पर आरोप है कि माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस को हल्का किया गया. आजतक को सरकारी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह बात सच लगती है.

केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने हजारों करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को हल्का बना दिया जिससे उसे विदेश जाने में आसानी हुई. इस बारे में खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है. आजतक–इंडिया टुडे को सरकारी सूत्रों ने जो जानकारी दी है उससे यह बात सच लग रही है.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि विजय माल्या के लुकआउट नोटिस को हल्का करके कहा गया कि अगर वह विदेश जाता है तो उसे पकड़ा न जाए बल्कि सिर्फ इसकी जानकारी दी जाए. सीबीआई ने 16 अक्टूबर, 2015 को माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था.

एजेंसी ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अनुरोध किया था कि माल्या यदि देश छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लिया जाए. लेकिन इसके एक महीने बाद ही नवंबर महीने में सीबीआई ने एक संशोधित सर्कुलर किया जिसमें इमिग्रेशन ब्यूरो से कहा गया कि वह सिर्फ श्माल्या के विदेश जाने और यात्रा के प्लान के बारे में सूचित करे.

इसके बाद माल्या नवंबर और दिसंबर में दो बार विदेश गया और लौट भी आया. इन लुकआउट नोटिसों के बाद भी माल्या तीन बार सीबीआई के सामने पेश हुआ था.

सूत्रों के मुताबिक अपनी पहली दो विदेश यात्राओं के दौरान माल्या ने सीबीआई को यह बताया था कि वह ि ब ज न े स मीटिंग के लिए विदेश जाता है. लेकिन तीसरी बार सीबीआई को माल्या की यात्रा की जानकारी भी नहीं मिली और उसके बाद वह ऐसा फरार हुआ कि आज सभी एजेंसियों के उसे भारत लाने में पसीने छूट रहे हैं.

उधर जेटली को लेकर दिए गए माल्या के बयान पर हंगामा जारी है. विजय माल्या ने कहा है कि वह लंदन जाने से पहले अरुण जेटली से मिला था. अब बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले पर ट्वीट किया है जो कई तरह के सवाल खड़े करता है.

विजय माल्या ने बुधवार को कहा कि वह भारत से रवाना होने से पहले वित्त मंत्री से मिला था. लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे माल्या ने कहा कि उसने मंत्री से मुलाकात की थी और बैंकों के साथ मामले का निपटारा करने की पेशकश की थी.

अरुण जेटली ने फेसबुक पर इस संबंध में सफाई देते हुए कहा, माल्या का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है. मैंने 2014 से अब तक उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया. वह राज्यसभा सदस्य थे और कभी–कभी सदन में आया करते थे. मैं सदन से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था, इसी दौरान वह साथ हो लिए. उन्होंने समझौते की पेशकश की थी, जिस पर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, यह प्रस्ताव बैंकों के साथ करें।

सहिष्णुता हिंदू धर्म का गुण हिंदू धर्म सर्वव्यापी : ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सहिष्णुता हिंदू धर्म का एक गुण है, हिंदू धर्म सर्वव्यापी है। सुश्री बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर रामकृष्ण मिशन की ओर से बेलुर मठ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, बंगाल सहिष्णुता की भूमि है। ेहदू धर्म लोगों से प्रेम करना सिखाता है,न कि भेदभाव। आगे आयें और देश में नई जागृति का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि वह शिकागो जाना चाहती थीं लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह नहीं जा सकी जहां स्वामी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा, इसके पीछे गहरी साजिश रची गयी थी। कुछ लोग चाहते थे कि मैं वहां न जाऊं। मैं आशा करती हूं कि जिन ताकतों ने मुझे वहां जाने से रोका वे स्वामी विवेकानंद के भाषण को पढ़ेंगे।

रूस पर अमेरिकी पाबंदी से भारत को झटका, अहम समझौते पर असर

नई दिल्ली। अमेरिका के काउंटर अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट (काट्सा) के कारण एस–400 बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद पर छूट की आस लगाए भारत को रूसी कंपनियों के साथ करीब आधा दर्जन अन्य समझौतों पर झटका लगने की आशंका है। भारत के साथ विभिन्न करार से जुड़ी छह से ज्यादा कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017 तक रूस से रक्षा क्षेत्र में भारत करीब 1.9 अरब डॉलर का आयात करता रहा है। इनमें से ज्यादातर खरीद मौजूदा सैन्य उपकरणों के कलपुर्जों और भारत में बनाए जा रहे उपकरणों की उप–प्रणालियों से जुड़ी है। भारत ने कई रूसी कंपनियों के साथ मिलकर कुछ साझा उद्यम भी शुरू किए हैं। इन पर ग्रहण लगने को लेकर भारत ने अपनी चिंता से अमेरिका को अवगत कराया है।

भारतीय थिंक टैंक गेटवे हाउस इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के

मुताबिक, भारतीय वायुसेना जल्द ही सुखोई बेड़े एसयू 30–एमकेआई को उन्नत करना चाहती है। एसयू–30 एमकेआई इस समय एन 011 एम पैसिव इलेक्ट्रानिक स्कैंड राडार सिस्टम (पेसा) से लैस है। इस सिस्टम की रूपरेखा रूसी कंपनी तिखोमोव साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ने तैयार की है।

वायुसेना अपने करीब 40 एसयू–30 एमकेआई को उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार सिस्टम (ऐसा) से लैस करना चाहती है। यह तकनीक फेजोट्रान ने विकसित की है। इस कंपनी को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस कारण सुखोई को उन्नत करने की योजना प्रभावित हो सकती है।

रूसी कंपनी उरलवगोंजाओद टी–90 और टी–70 टैंक के सैन्य हार्डवेयर की बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी है। यूनाइटेड शिपबिल्डिग कॉरपोरेशन का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ नागरिक व सैन्य शिप बिल्डिंग के लिए सहयोग है। रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व के शीर्ष सैन्य हार्डवेयर उपकरण के आयातकों में शामिल भारत की उपकरणों की खरीद के लिहाज से रूस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है।

(पृ. 1 का शेष) . . . **राजधानी में निकला मोर्हरम** . . . बढ चढ़ कर हिस्सा लिया।

आपको बताते चले की इस्लामिक महीने की पहली तारीख के मोहर्रम का आगाज आज से शुरू हो गया है। पहली मोहर्रम के जुलुस में शाही जरी की तमाम लोगों ने ज़्यारत की और बढ़ चढ़ कर जुलूस में हिस्सा लिया।

जुलुस शाम 6 बजे बड़े इमामबाड़े से निकल कर रात 11 बजे छोटे इमामबाड़ें में समाप्त हुआ। जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के कई आलाधिकारियों के साथ शहर के कप्तान कलानिधि नैथानी और जिलाधिकारी कौशल राज खुद मौजूद रहे।

(पृ. 1 का शेष) . . . **पीएम मोदी 17 को** . . . बैठक कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शहर में विशेष स्वच्छताअभियान चलाने का निर्देश दिया।

संयोग से 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन–पूजन करेंगे। साथ ही करीब 5,000 स्कूली बच्चों के साथ अपने जीवन से जुड़ी फिल्म 'चलो जीते हैं' देखेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, हालांकि अभी कार्यक्रम स्थल का फिलहाल चयन नहीं हुआ है। सुरक्षा कारणों से पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में फिल्म दिखाई जा सकती है। भाजपा भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुट गई है।

(पृ. 1 का शेष) . . . **कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश** . . . 62 करोड़ रु. भेजवा देती तो यहां बंधा बन जाता और यहां की जनता आज नाराज नहीं होती। यहां की जनता सिर्फ बंधा मांग रही है कि मेरे क्षेत्र में बंधा बन जाए जिससे हम लोग सुरक्षित हो जाए। सीएम को उस जगह यहां के अधिकारी ले जा रहे हैं ना सही बात सीएम को यहां के अधिकारी बता रहे है। ऐसे में 2019 में भाजपा को नुकसान सहना पड़ेगा और हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे।

अगर बसपा सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो भाजपा की स्थिति और खराब हो सकती है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महगाई के मुद्दे पर कहा कि आम आदमी का उड़ाया जा रहा है मजाक। महगाई में लोग टमाटर ज्यादा खाते है।

कैबिनेट मंत्री ने राहुल के कैलाश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब विपत आती है तो सब हनुमान चालीसा है पढ़ते

जब विपति आती है तो मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा का सहारा लेते है राहुल भी सत्ता से दूर है

कोई पार्टी यह कहे की वह जातिवादी नही है तो वह झूठ बोल रही है।

(पृ. 1 का शेष) . . . **राजधानी में निःशुल्क**. . . 1997 में अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निरूशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गई थी, जिसमें 50 फीसदी स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग 45 फीसदी राजस्थान अनुसूचित जाति के तथा 5 फीसदी स्थान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित ौध्च्छै कोचिंग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निरूशुल्क चलाई जाती है। इसमें रहने खाने से लेकर सभी चीजें निःशुल्क है।

साथ ही उन्होंने कहा कि यह ऐसा संस्थान है। जहां पर हर चीज की साफ–सफाई है और बेहद ही अच्छी व्यवस्था है। यहां से काफी संख्या में बच्चें सेलेक्ट होकर IAS/PCS बनते हैं। वहीं इस मौके पर समाज कल्याण आयुक्त चंद्र प्रकाश ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है, जिसमें ढाई सौ बच्चें इस बार सेलेक्ट हुए हैं।

(पृ. 1 का शेष) . . . **चुनाव आयोग के निर्देश** . . . इससे भ्रष्टाचार और दल बदल को बढ़ावा मिलेगा। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र नागरिकों के भरोसे से मजबूत होता है जो कि पवित्रता, निष्ठा, ईमानदारी और सत्यपरायणता के स्तंभ पर टिका है। इस पकड़ को मजबूत बनाना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ रहे और लोकतंत्र गलत ताकतों के खिलाफ अभेद्य दुर्ग की तरह ऊंचाई से खड़ा रहे। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करना पहली निगाह में बुद्धिमत्तापूर्ण लगता है, लेकिन अगर उसकी पड़ताल की जाए तो ये आधारहीन दिखता है क्योंकि इसमें ऐसे चुनाव में मतदाता की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। शुरुआत में ये सोच आकर्षक लग सकती है लेकिन इसके व्यवहारिक प्रयोग से अप्रत्यक्ष चुनावों में समाहित चुनाव निष्पक्षता समाप्त होती है। वह भी तब जबकि मतदाता के मत का मूल्य हो और वह मूल्य ट्रांसफरेबल हो। ऐसे में नोटा एक बाधा है। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से न सिर्फ संविधान के दसवीं अनुसूची मे दिये गए अनुशासन का हनन होता है (अयोग्यता के प्रावधान) बल्कि दल बदल कानून में अयोग्यता प्रावधानों पर भी विपरीत असर डालता है। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने 2014 और 2015 में दो अधिसूचनाएं जारी की थीं

(पृ. 1 का शेष) . . . **300 से अधिक दवाईयों** . . . लगा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बताया गया कि डीटीएबी के 328 दवाओं की जांच करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बैन का असर सैरिडॉन, एस–प्रॉक्सिवोन, निमिलाइड फेन, जिंटैप पी, एमक्लॉक्स, लिनॉक्स एक्स टी और जैथरिन ए एक्स जैसी दवाओं पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरकार ने सिर दर्द के लिए सेरिडॉन को तो बंद कर दिया लेकिन डीकोल्ड टोटल, फेंसेडाइल और ग्राइलिंकट्स को बंद नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दर्द निवारक और कफ सिरप जैसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ऐसी 328 दवाओं पर रोक लगा दी है। इनमें कई ऐसी दवाएं हैं, जो डॉक्टर की पर्ची के बिना ही दुकान पर मिल जाती थी। ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाएं हैं। इससे एबॉट, पीरामल, मैक्लिऑड्स, सिप्ला और ल्यूपिन जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कमाई प्रभावित होगी। अगर इन 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी यह दवाएं मेडिकल स्टोर पर पाई जाती है

(पृ. 1 का शेष) . . . **पेट्रोल, डीजल के दामों** . . . है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है। गोयल ने कहा कि सरकार को कोई भी कदम दीर्घकाल में उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर उठाना चाहिए न कि अल्पकालीन हितों को ध्यान में रखना चाहिए। कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गोयल ने उदाहरण देते हुए कहा, ''रुपये की विनिमय दर में गिरावट थामने के लिये आरबीआई ने 2013 में विदेशी मुद्रा जुटाने को लेकर प्रवासी भारतीयों को बांड (एफसीएनआर (बी) जारी किये गये। इसके परिपक्व होने पर हमने 2016–17 में इसका भुगतान किया। इसी प्रकार, संप्रग शासन 1.5 लाख करोड़ रुपये का तेल बांड जारी किया गया जिसमें से हमने अभी 50,000 करोड़ रुपये दिया है।''

रेलवे से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने मांग के साथ किराये में वृद्धि (डायनेमिक किराया) में बदलाव की संभावना से इनकार किया। हालांकि उन्होंने इस मामले में गौर करने का जरूर आश्वासन दिया। त्यौहारों के समय पक्की टिकट मिलने की समस्या से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मालगाड़ियों के लिये अलग गलियारा बनने से चीजें कुछ बेहतर होगी। रेल मंत्री ने इस मौके पर 'रेल समन्वय पोर्टल' और 'एप' जारी किया।

(पृ. 1 का शेष) . . . **माल्या–जेटली को बात** . . . उसी बातचीत में हो सकता है कि जेटली ने माल्या को देश छोड़ने की सलाह दी होगी. एबीपी न्यूज से बात करते हुए पुनिया ने कहा, जब विजय माल्या गए हैं उससे दो दिन पहले सेंट्रल हॉल में मैंने देखा कि विजय माल्या अलग से जेटली से बहुत गंभीर वार्ता कर रहे हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि मैं वित्त मंत्री से मिला था और सेटलमेंट करना चाहता हूं. इन्होंने (जेटली ने) राय दी कि अब हिंदुस्तान से चले जाओ वर्ना जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ी हैं. विजय माल्या ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था. लंदन के वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर उन्होंने कहा, मैंने पूरे मामले को सुलझाने के लिए भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री जेटली से मुलाकात की थी. मैं बैंकों का बकाया कर्ज चुकाने के लिए तैयार था, लेकिन बैंकों ने मेरे सेटलमेंट को लेकर सवाल खड़े किए.।

(पृ. 1 का शेष) . . . **दारोगा और सिपाहीं** . . . गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह दिल्ली में एक बैठक में जा रहे थे. इस दौरान वह शहर से गुजरते वक्त सेक्टर 30 के आम्रपाली पुलिस चौकी पर पहुंचे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय पाल शर्मा के मुताबिक डीजीपी दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चौकी पहुंचे थे . उस वक्त प्रभारी निरीक्षक और कांस्टेबल तैनात थे. एसएसपी ने बताया कि एसआई और कांस्टेबल ने ड्यूटी के समय अपनी टोपी नहीं पहन रखी थी.

उन्होंने उसे अपनी जिप्सी में रखा हुआ था. यह दोनों डीजीपी के वाहन को नहीं पहचान सके और इनका पूरा रवैया भी लापरवाही भरा था. शर्मा ने इस बात को खारिज कर दिया कि एसआई और कांस्टेबल ने डीजीपी के साथ सवाल–जवाब किया था. शर्मा ने पुष्टि की कि उन दोनों ने डीजीपी को पहचाना था और वह वाहन के निकट भी पहुंचे थे.

पांचवा टेस्ट हारने के बाद भावुक हो गए ऋषभ पन्त, कह दी दिल छूने वाली बात

लंदन। पांचवा टेस्ट मैच हारने के बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम के धुआंधार खिलाड़ी ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी। भावुक होते हुए अपने बयान में इतने कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया था। उसने कहा कि यकीनन जिस तरीके का प्रदर्शन हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों का इस सीरीज में रहा वह बेहद ही निराशाजनक है। लेकिन इस हार से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरीके का प्रदर्शन दोबारा ना दोहराएं।

उसके बाद जब रिपोर्टर ने पंथ से यह पूछा कि अगर आप चाहते तो, एक बड़ी पारी आराम से खेलकर भारतीय टीम को जिता सकते थे। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस बात का जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं क्रीज पर ज्यादा देर तक रहता। तो अपनी टीम को जीत की तरफ ले कर जा सकता था। लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से खराब शॉट ने मेरी पारी को समेट कर रख दिया। जिसके लिए मैं अपने आपको कहीं ना कहीं इस हार का जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन मैं इस गलती से सीख लेकर आगे अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता रहूंगा। पंत इस बयां में बहुत भावुक दिखे। कारण भी था कि 114 रन की पारी खेलकर भी वह अपनी टीम को नहीं जीता सके।

सैनिकों की कटौती पर कांग्रेस ने मोदी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सेना में जवानों की संख्या कम किए जाने की कथित योजना से संबंधित कुछ खबरों का हवाला देते हुए बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि क्या डेढ़ लाख सैनिकों की कटौती की जा रही है? पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनुसिघवी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी र्चचा हो रही है, लेकिन राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने वाले खामोश हैं। उन्होंने कहा, खबरें आ रही हैं कि सरकार डेढ़ लाख सैनिकों की कटौती करने जा रही है। राष्ट्रवाद पर लेक्चर देने वाले लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन ये खामोश हैं। शहादत सैनिकों की होती है और भाजपा अपना महिमामंडन करती है। सिघवी ने सवाल किया, क्या सरकार डेढ़ लाख सैनिकों की कटौती कर रही है? क्या यह इसलिए किया जा रहा है कि इससे पांच–सात हजार करोड़ रुपये बचाकर उपकरणों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा?

एनबीसीसी बनाएगा आम्रपाली के फ्लैट

नई दिल्ली। आम्रपाली की आधी–अधूरी भवन परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली की परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण को निर्देश दिया है कि वह आम्रपाली की कर्जमुक्त संपत्तियों की नीलामी करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक एस्क्रो खाता भी खोलने को कहा है जिसमें ऐसी संपत्तियों की बिक्री से मिला धन जमा किया जाएगा और इसमें से एनबीसीसी को निर्माण शुरू करने के लिए भुगतान किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में जोतिंद्र स्टील समेत सभी 46 कंपनियों की 2008 के बाद की बैलेंस शीट, बैंक खाते एवं कागजात फोरेंसिक लेखा–परीक्षकों को देने के भी निर्देश दिए हैं।

चीन में हर साल भोजन बनते हैं करोड़ों कुत्ते

वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसके तहत इंसानों के भोजन के लिए कुत्तों और बिल्लियों के वध पर रोक लगाई जाएगी. कुत्ता एवं बिल्ली मांस व्यापार निषेध कानून 2018 का उल्लंघन करने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर (3,50,000 से अधिक रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा.एक अन्य प्रस्ताव में सदन ने चीन, दक्षिण कोरिया और भारत सहित सभी देशों से कुत्तों और बिल्लियों के मांस का व्यापार बंद करने का अनुरोध किया.

कांग्रेस सदस्य क्लाउडिया टेनी ने कहा, ''कुत्ते और बिल्ली साथी और मनोरंजन के लिए होते हैं. दुर्भाग्य से, चीन में हर साल इंसान के भोजन के लिए एक करोड़ से अधिक कुत्तों को मार दिया जाता है.''

उन्होंने कहा, ''इन चीजों के लिए हमारे करुणामय समाज में कोई स्थान नहीं है। यह विधेयक अमेरिका के मूल्यों को परिलक्षित करता है और सभी देशों को एक सख्त संदेश देता है कि हम इस अमानवीय और क्रूर बर्ताव का साथ नहीं देंगे.''

प्रस्ताव में चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाइलैंड, फिलिपीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, भारत और अन्य देशों की सरकारों से कुत्तों और बिल्लियों के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को अपनाने और उसे लागू करने का अनुरोध किया गया है.

संक्षिप्त समाचार

सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने बुधवार को अपने चमकदार कॅरियर को अलविदा कहने का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में वह काफी हॉकी खेल चुके हैं और अब युवाओं के लिए जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। सरदार ने कहा कि उन्होंने एशियन गेम्स में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह फैसला किया जिसमें भारत अपने खिताब का बचाव करने में असफल रहा और उसे कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। सरदार की उम्र भी बढ़ रही है और अब उनके खेल में पहले जैसी फुर्ती देखने को नहीं मिलती जिससे एशियन गेम्स के दौरान उनके प्रदर्शन की काफी आलोचना हुई।

आतंकियों ने की सुरक्षा बलों पर गोलीबारी

जम्मू। फिदायीन दस्ते का हिस्सा माने जा रहे जैश–ए–मोहम्मद के तीन संदिग्ध आतंकवादियों ने बुधवार को जम्मू–कश्मीर में घुसपैठ की और राज्य के मुख्य राजमार्ग पर सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की। इसके बाद वे शहर के पास के एक जंगल में भाग गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने रोके गए एक ट्रक से सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया। यह वाकया उस वक्त हुआ जब जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले राजमार्ग पर झाजर कोटली में एक जांच चौकी से गुजरने के बाद ट्रक रफ्तार पकड़ रहा था।

महिलाओं के लिए पैन कार्ड नियमन में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बुधवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड नियमन में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है ताकि अकेले रहने वाली महिलाओं को अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवाने में पूर्व पति के नाम का उल्लेख नहीं करना पड़े। मेनका ने ट्वीट कर कहा,मुझे यह जानकार खुशी हुई है कि वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड नियमन में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है ताकि अकेले रहने वाली महिलाओं को अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवाने में पूर्व पति के नाम का उल्लेख नहीं करना पड़े। दरअसल, मेनका गांधी ने पैन कार्ड नियमन में बदलाव की मांग करते हुए जुलाई महीने में वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए पैन कार्ड बनवाने में उनके पिता का नाम न लिखने के विकल्प की व्यवस्था की जाए।

'स्वच्छता ही सेवा आंदोलन' से जुड़ें देशवासी : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों से अपील की कि श्स्वच्छता ही सेवा आंदोलनश 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलेगा। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि भारी संख्या में 15 सितंबर को 9:30 बजे सुबह 'स्वच्छता ही सेवा आंदोलन' से जुड़ें। पीएम ने कहा, मैं बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और फेमस लोगों समेत सभी को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि दूसरों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

पीएम मोदी ने 15 सितंबर से श्स्वच्छता ही सेवा आंदोलनश के शुभारंभ की घोषणा की और इस आंदोलन को दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि बताया। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में सभी से स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत बनाने के प्रयासों को मजबूत करने का आग्रह किया।

कर्मचारियों को तय समय पर दें प्रमोशन, इंक्रीमेंट व पेंशन लाभ : सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां लटकाने, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने में दौड़ाने और इंक्रीमेंट के लिए जी–हुजूरी कराने की परंपरा का संज्ञान लिया।

उन्होंने अफसरों की बैठक में सरकारी कर्मियों को मिलनेवाली सुविधा व लाभ से जुड़े हर बिंदु की विस्तार से समीक्षा की। तय समयसीमा में सभी लाभ दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की शिकायतों पर इतनी चिंता दिखाई हो।

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा के दौरान कर्मचारियों की पदोन्नति, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (इंट्री), इंक्रीमेंट, अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्त लाभ व एलटीसी आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नतियां 'ऑटो मोड' में होनी चाहिए और उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सरकारी सेवकों को तय समय पर पदोन्नतियां सुनिश्चित कराई जाएं। कोई भी डीपीसी लंबित न रखी जाए।

अमेरिका ने माना, भारत में अल्पसंख्यकों को मिली है धार्मिक आजादी

वाशिंगटन। भारत विश्व का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि जीवंत लोकतंत्र भी है। वहां के संविधान ने अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी समेत सभी अधिकार स्थापित किए हैं। विदेश मंत्रालय में दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की प्रधान उपसहायक सचिव एलिस वेल्स ने भारत समेत अन्य देशों के मानवाधिकार पर बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के एलन क्रांस्टाड ने एलिस से सवाल पूछने के दौरान भारत में धार्मिक आजादी पर चिंता जताई थी। एलन ने पूछा, श्मैं खासतौर पर मानव अधिकारों के बारे में जानना चाहता हूं। आपके विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में भी मानवाधिकार के व्यापक उल्लंघन की चर्चा की गई है। इनमें से कुछ मामलों के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया गया है। भाजपा शासन में धार्मिक आजादी से जुड़े मसलों का भी रिपोर्ट में जिक्र है।श इसके जवाब में एलिस ने कहा कि भारतीय संविधान ने वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया है।

नेतन्याहू ने पीएलओ दफ्तर बंद करने के अमेरिकी निर्णय को सराहा

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को वाशिंगटन में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) के कार्यालय को बंद करने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय का स्वागत किया। विदेश विभाग ने फिलिस्तीन द्वारा इजरायल के साथ सीधी वार्ता को आगे ना बढ़ाने का हवाला देते हुए सोमवार को अपने इस निर्णय की घोषणा की।

बयान में इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इजरायलियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में उठाने के फिलिस्तीन के प्रयास का भी उल्लेख किया गया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी उनके बयान के हवाले से बताया, "अमेरिका ने वाशिंगटन स्थित पीएलओ दफ्तर के संबंध में सही निर्णय लिया है।"

उन्होंने कहा, "इजरायल अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करता है, जिसमें फिलिस्तीनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्ता से उनका इनकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजरायल पर हमला करने से शांति नहीं बढ़ेगी।" फिलिस्तीन ने अमेरिकी कदम की निंदा की है।

पीएलओ के महासचिव साएब ऐरेकात ने एक बयान में कहा, "यह भड़काऊ कदम बताता है कि अमेरिका इजरायल के अपराधों और फिलिस्तीन के लोगों और जमीन पर उसके हमलों का बचाव करने के साथ–साथ बचे हुए क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के खिलाफ काम कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तोड़ना चाहता है।"

ट्रंप प्रशासन मध्य–पूर्व में शांति स्थापित करने की अपनी बहु–प्रतीक्षित योजना को सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है लेकिन जेरूशलम को इजरायल की राजधानी मानने के ट्रंप के विवादित फैसले के बाद फिलिस्तीन के नेताओं ने ट्रंप के राजदूतों से वार्ता करने से इनकार कर दिया है।

फ्लोरेंस तूफान से हिला यूएस बना हुआ है परमाणु खतरा

वाशिंगटन। फ्लोरेंस तूफान ने अमेरिका में भयंकर तबाही मचा रखा है। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एहतियातन तटीय इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं, श्रेणी–5 का तूफान फ्लोरेंस अमेरिका के तट तक पहुंच चुका है। जिससे 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है।

इस कारण वर्जीनिया, उत्तर और दक्षिण कैरलाइना के तटीय इलाकों से 15 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।

बीजेपी को लेकर अखिलेश ने दिया ये बड़ा बयान, खलबली

गोरखपुर। बीजेपी को लेकर अखिलेश ने दिया ये बड़ा बयान, मचेगी खलबली लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर हार पर एक बड़ा बयान दिया है. कहा है कि गोरखपुर की हार से बौखलाए लोग छात्रसंघ चुनाव से डर गये है. हार के भय से बुरी तरह आहत होकर छात्रों से बदसलूकी की. अखिलेश ने कहा कि लगता है गोरखपुर लोकसभा उप–चुनाव में हारने के बाद अब कुछ लोगों को गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो चुनाव टाल रहे हैं. ये चुनाव से पहले ही हार मान लेने का सबूत है. छात्रों से उनका अधिकार छीनना अलोकतांत्रिक है. बता दें कि गोरखपुर में मंगलवार को गोरखपुर में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया।

देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री से की थी मुलाकात : विजय माल्या

लंदन। प्रत्यर्पण मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान माल्या ने कहा– देश छोड़ने से पहले मैंने वित्त मंत्री से मिला था। बैंकों को मेरे सेटलमेंट ऑफर मानने से इंकार कर दिया था। वकील ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई ने माल्या के खिलाफ केस न दर्ज करने पर बैंकों को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

रिपोर्ट्स से मिली जानाकारी के मुताबिक, लंदन कोर्ट ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल का वीडियो भी देखा। यहीं माल्या को प्रत्यर्पण के बाद रखा जाना है। माल्या के वकीलों ने भारतीय जेलों की बुरी स्थिति का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण भारत न करने की अपील की थी। हालांकि, तब जज ने भारतीय अधिकारियों से आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 का एक वीडियो तैयार करने के लिए कह दिया था।

माल्या का कहना है कि उसने कर्ज के निपटारे के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट को इस साल जून में प्लान दिया था। वह अपनी 13,900 करोड़ रुपए की संपत्ति की बिक्री के लिए राजी हुआ था।

दिसंबर से पहले 80 फीसद गंगा साफ हो जायेगी : नितिन गडकरी

लखनऊ। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है की दिसंबर से पहले पहले अस्सी प्रतिशत गंगा साफ हो जाएगीद्य गडकरी ने ये बात यूपी के बागपत में कही जब वो कार्यक्रम में शामिल होने आये थेद्य गडकरी ने कहा की गंगा स्वच्छता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैद्यनितिन गडकरी ने कहा की "गंगा स्वच्छता में तीव्र गति से काम करने के लिए हम यूपी सरकार को पर्याप्य धन उपलब्ध करायेगेद्य उन्होंने कहा कि अगस्त में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा नदी के किनारे सफाई कार्य की समीक्षा की

है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 में कुंभ मेला शुरू होने से पहले गंगा नदी को साफ करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गंगा सफाई के लिए 1700 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इलाहाबाद में चार नदी पोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्रालय नवंबर के अंत तक इलाहाबाद और वाराणसी के बीच 40 लोगों की क्षमता वाली एयरबोट सेवाएं भी लॉन्च करेगा। सड़क निर्माण पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सड़क निर्माण पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तो विकास की गति भी तेज होगी।

पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के बिशप को लिखा पत्र

वेटिकन सिटी। पोप फ्रांसिस फरवरी के शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर में हर बिशप सम्मेलन के अध्यक्षों को बुला रहे है ताकि वे पादरी यौन शोषण को रोक सकें और बच्चों की रक्षा कर सकें. इससे पहले उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी कि कैथोलिक चर्चों में यौन शोषण और अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का विश्वास चर्च पर से उठ रहा है.

पोप फ्रांसिस के अनुयायियों द्वारा बताया गया कि एक दिन पहले पोप ने यौन शोषण के आरोपों के कारण बदनाम हुए चर्चों के अधिपतियों से मिले थे. उल्लेखनीय है कि वेटिकन आरोपों से जूझ रहा है कि कैथोलिक चर्च के नेता ने अमेरिकी कार्डिनल के दुर्व्यवहार को छिपाने में मदद की. हालॉकि वेटिकन ने आर्कबिशप कार्लो मारिया विगानो के आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ष्स्पष्टीकरणष का वादा किया है जो शायद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्रांसिस की बैठक के बाद कुछ समय बाद आएगा.

समाने आया अक्षय की `केसरी' का पहला पोस्टर, सारागढ़ी सैनिकों को दी श्रद्धाजंलि

जो देखते ही देखते चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बात दें कि 'केसरी' 1897 में हुए सारागढ़ी के युद्ध पर बनी है जिसमें सिखों ने अपना लहू देकर जीता था। कुल 21 सिखों ने 12 हजार पठानों को खदेड़ दिया था। सबसे पहले अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा और करण जौहर ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया, जिसके बाद देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गया।

अक्षय कुमार ने पोस्ट को शेयर करते सारागढ़ी दिवस को रुप में सिम्बलाइज किया था और 21 सिखों को श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि आज मेरी पगड़ी भी केसरी जो बहेगा मेरा वो लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। बता दें कि 'केसरी' अगले साल 21 मार्च 2019 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार फिल्म में लीड रोल निभाने वाले हैं। एक्टर ने सारागढ़ी कैप्शन के साथ पोस्टर को शेयर किया। अक्षय के फैंस ने भी पोस्टर को लेकर काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। बता दें कि सारागढ़ी युद्ध आज के दिन यानी 12 सिंतबर को हुआ था। कहा जाता है कि सिख रेजीमेंट के उन शूरवीर बहादुर सैनिकों की याद दिलाता है, जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी किले की रक्षा करके 10 हजार पठानों का मुकाबला करते हुए शहादत दी थी।

गौरतलब है कि ये अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म का पहला पोस्टर है। इन पोस्टर्स में अक्षय कुमार यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनके साथ और बहुत सारे सिपाही नजर आ रहे हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के ट्विटर हैंडल से ये पोस्टर्स शेयर किए गए हैं। एक पोस्टर में अक्षय कुमार और अन्य सैनिक हाथ में बंदूक उठाए खड़े हैं, वहीं दूसरे पोस्टर्स में सभी सैनिक बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

नासा के मंगल पर भेजे जाने वाले मानव मिशन पर खतरे के बादल

नई दिल्ली। नासा द्वारा मंगल की जानकारी लेने के लिए भेजे गए इनसाइड लैंडर को लॉन्च किए हुए अभी महज छह माह पूरे हो गए हैं। यह 26 नवंबर को मंगल पर पहुंचेगा। यह यान मंगल की जमीन की भीतरी सतह की जांच करेगा। इस यान को इनसाइट (इंटीरियर एक्प्लोरेशन यूजिंग साइस्मिक इनवेस्टिगेशन जीयोडसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट) का नाम दिया गया है। यदि मिशन कामयाब रहता है तो मंगल ग्रह से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन समय के साथ–साथ इस ग्रह की अपनी समस्याओं की पहचान भी होने लगी है। अब वैज्ञानिकों ने यहां पर आने वाली समस्याओं की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में शामिल तमाम चीजें मंगल मिशन पर जाने वाले

आमिर खान को रिप्लेस कर जॉन ने बनाई 'सरफरोश' में जगह, बनेगा सीक्वेल

फैंस से लेकर आलोचकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की थी। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग से लेकर फिल्म के गानों तक ने धमाल मचा दिया था। 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को जॉन मैथ्यू मैथन ने प्रोड्यूस किया था।

अब 19 साल बाद जॉन मैथ्यू मैथन अपनी मच ऑवेटिड फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं लेकिन मैथ्यू नहीं चाहते कि फिल्म सरफरोश में आमिर खान दोबारा एसीपी अजय सिंह राठौड का रोल प्ले करें। मेकर्स इस बार किसी और फिल्म मे काम करने का मौका देना चाहते हैं। मेकर्स की माने तो स्क्रिप्ट उनके पास तैयार है बस अब किसी यंग फेस की तलाश है जो फिल्म के रोल में फिट बैठ सके।

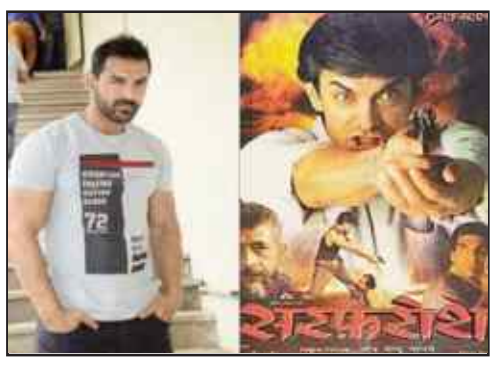

बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम ने सत्यमेव जयते और परमाणुरू द स्टोरी ऑफ पोखरण फिल्मों से बड़े पर्दे पर वापसी की है जबकि फिलहाल वो रोबी ग्वेल के जासूस–थ्रिलर फिल्म 'रा' की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में जॉन ने इस बात का खुलासा किया कि वो आमिर खान की फिल्म 'सरफरोश' में काम करने वाले हैं। जॉन का कहना है कि आमिर खान उन अभिनेताओं में से है जिनको मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूं और फॉलो भी करता हूं। कुछ समय पहले फिल्म के सीक्वल को लेकर आमिर खान ने कहा था कि सरफरोश मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक हैं। यदि सरफरोश का सीक्वल बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी।

आरटीआई जानकारी से खुलासा हुआ राजभवन में लगे हैं 106 एसी

लखनऊ। आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में सामने आया है कि यूपी के राजभवन में कुल 24 कमरे हैं। इनमे 10 अतिथि कक्ष तथा 14 कार्यालय कक्ष हैं। इनमें कुल 85 कर्मी कार्यत हैं। वहीं कुल 106 एसी लगे हुए हैं। समाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिवस्ट नूतन ठाकुर द्वारा डाली गई आरटीआई के जवाब में प्रदेश के जन सूचना अधिकारी संजय दीक्षित ने ये जानकारी दी है।

सूचना के अनुसार राज भवन के शासकीय भवन में कुल 24 कमरे हैं। इनमे 10 अतिथि कक्ष तथा 14 कार्यालय कक्ष हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य भवन एनेक्सी में प्रथम तल पर एक सचिव आवास है। साथ ही राज्यपाल तथा उनके परिवार के निजी प्रयोग के लिए 4 कमरे हैं।इन कमरों तथा सभागार में कुल 106 एसी लगे हैं। पूर्व में नूतन द्वारा मांगी गयी एक अन्य सूचना में बताया गया था कि राज भवन में कुल 86 कर्मी काम करते हैं।इ नमें एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव तथा एक विधि परामर्शी हैं। साथ ही 04 विशेष कार्याधिकारी, 04 निजी सचिव तथा अन्य सचिवालयीय सहायक हैं। इनके अलावा 1 शेफ, 1 स्टीवर्ड, 6 चालाक, 3 वरिष्ठ अनुसेवक तथा 19 अनुसेवक हैं। इनके साथ 16 बेयरर, 5 सहायक बेयरर, 3 मेट, 2 कुक, 1 टेलर, 1 रजक तथा 5 सफाई कर्मी हैं। प्रमुख तथा विशेष सचिव के वेतन शासन से मिलते हैं जबकि अन्य कर्मियों का मासिक वेतन रु० 39,70,530 है।

एनएसजी पर भारत को मिला यूएस का साथ

वाशिंगटन। परमाणु आपूर्ति कर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता के लिए भले ही चीन अड़ंगा लगा रहा हो, लेकिन अमेरिका भारत के समर्थन में है। गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन के वीटो के कारण भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन अमेरिका एनएसजी में भारत की सदस्यता की वकालत करता रहेगा, क्योंकि भारत इसके सभी मानदंडों को पूरा करता है।

इससे पहले नई दिल्ली में छह सितंबर को हुई टू प्लस टू वार्ता के दौरान भी भारत और अमेरिका एनएसजी की सदस्यता जल्द–से–जल्द दिलाने के लिए एकसाथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए थे।

फिर गिरी सलमान पर गाज, अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। बिहार की एक अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि सलमान के खिलाफ ये आदेश मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीजीएम ने दिया है जिसके बाद मिठनापुर थाने में केस दर्ज होगा।यह पूरा मामला उनकी फिल्म लवरात्रि से जुड़ा है, जिसको लेकर सलमान खान के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म लवरात्रि के मामले में सलमान के साथ–साथ 76 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। लवरात्रि फिल्म की टीम पर संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का

आरोप है।

आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की सीजीएम अदालत में सलमान खान के खिलाफ केस दाखिल किया गया है। इस केस में सलमान खान, फिल्म के लीड हीरो आयुष शर्मा, वरीना हुसैन, अंशुमान झा, राम कपूर समेत 76 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया है।

इससे पहले भी फिल्म के नाम को लेकर काफी हंगामा किया जा चुका है। 'लवरात्रि' को लेकर वीएचपी ने कहा था कि फिल्म से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग नहीं होने दी जाएगी।

गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में एक जोड़े की लव स्टोरी दिखाई है।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी एवं संपादक
हेमन्त कुमार मिश्रा
द्वारा पिन वर्क पब्लिकेशन हाउस, दादाबाड़ी कम्पाउन्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

संपादक
हेमन्त कुमार मिश्रा

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद लखनऊ न्यायालय होगा।

इस अंक में प्रकाशित समाचारों में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर सात दिन के अंदर खंडन भेजे अन्यथा समाचार "सत्य" माना जायेगा।
संपादक

crimereview2012@gmail.com
मो: 9454552222